RNI No. UPHIN/2000/3766 ● ISSN No. 2581-3528 ₹ : 20

केशव संवाद

चैत्र-वैशाख, विक्रम सम्वत् 2080 (अप्रैल-2023)

स्वस्थ विश्व का आधार बना 'मिलेट्स'

अप्रैल 2023, चैत्र-वैशाख विक्रम सम्वत् 2080

हिन्दी पंचांग

HinduCalendars.in

SUN रविवार	MON सोमवार	TUE मंगलवार	WED बुधवार	THU गुरुवार	FRI शुक्रवार	SAT शनिवार
30 वैशाख शु.१०						1 कामदा एकादशी चैत्र शु.११
2 चैत्र शु.१२	3 सोम प्रदोष चैत्र शु.१३	4 महावीर जयंती चैत्र शु.१३	5 चैत्र शु.१४	6 शिवाजी महाराज पुण्यतिथी हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा	7 गुड फ्राइडे वैशाख मासारंभ वैशाख कृ.१	8 वैशाख कृ.२
9 गणेश संकष्ट चतुर्थी ईस्टर संडे वैशाख कृ.३	10 वैशाख कृ.४	11 महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती वैशाख कृ.५/६	12 वैशाख कृ.७	13 कालाष्टमी वैशाख कृ.८	14 डॉ.आंबेडकर जयंती वैशाख कृ.९	15 वैशाख कृ.१०
16 बरुथिनी एकादशी वैशाख कृ.११	17 सोम प्रदोष वैशाख कृ.१२	18 वैशाख कृ.१३	19 दर्श अमावस्या वैशाख कृ.१४	20 खग्रास सूर्यग्रहण अमावस्या	21 चंद्रदर्शन वैशाख शु.१	22 अक्षय तृतीया रमज़ान ईद वैशाख शु.२
23 विनायक चतुर्थी वैशाख शु.३	24 वैशाख शु.४	25 श्री आद्य शंकराचार्य जयंती वैशाख शु.५	26 गंगापूजन वैशाख शु.६	27 वैशाख शु.७	28 दुर्गाष्टमी वैशाख शु.८	29 सीता नवमी वैशाख शु.९

HinduCalendars.in

अप्रैल 2023 त्यौहार

01 शनिवार	कामदा एकादशी	02 रविवार	वैष्णव कामदा एकादशी	03 सोमवार	प्रदोष व्रत
05 बुधवार	अन्वाधान	06 बृहस्पतिवार	हनुमान जयन्ती, हनुमान जन्मोत्सव, चैत्र पूर्णिमा, इष्टि	09 रविवार	विकट संकष्टी चतुर्थी
14 शुक्रवार	मेष संक्रान्ति, सोलर नववर्ष	16 रविवार	बरूथिनी एकादशी	17 सोमवार	प्रदोष व्रत
19 बुधवार	दर्श अमावस्या, अन्वाधान	20 बृहस्पतिवार	सूर्य ग्रहण *संकरित, इष्टि, वैशाख अमावस्या	21 शुक्रवार	चन्द्र दर्शन
22 शनिवार	परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया	27 बृहस्पतिवार	गंगा सप्तमी	29 शनिवार	सीता नवमी

केशव संवाद

RNI No. UPHIN/2000/3766

ISSN No. 2581-3528

अप्रैल, 2023

वर्ष : 23 अंक : 04

अणंज कुमार त्यागी
अध्यक्ष
प्रे. शो. सं. न्यास

संपादक
कृपाशंकर

सह संपादक
डॉ. प्रदीप कुमार

संपादक मंडल
डॉ. प्रियंका सिंह, डॉ. अखिलेश मिश्र, डॉ. नीलम कुमारी, प्रो. अनिल निगम, डॉ. मनमोहन सिंह, अनीता चौधरी, अनुपमा अग्रवाल, अमित शर्मा

पृष्ठ संयोजन
वीरेंद्र पोखरियाल

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
सी-56/20 सेक्टर-62, नोएडा -201301
फोन न. 0120 4565851, 2400335
ईमेल : keshavsamvad@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

स्वामी पंकज कुमार की ओर से मुद्रक/प्रकाशक सुखवीर प्रकाश द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा केशव भवन 105, आर्यनगर सूरजकुंड रोड मेरठ से प्रकाशित

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा मेरठ की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा। संपादक

विषय सूची

संपादकीय..04

स्वस्थ विश्व का आधार बना 'मिलेट्स' –प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी.... 05

बिहार से बंगाल तक रामनवमी को फिर बनाया गया... – मृत्युंजय दीक्षित............08

आर्थिक प्रगति में शुचितापूर्ण नीतियों का अपनाया... – प्रहलाद सबनानी 10

डिग्रियों पर विवाद और ज्ञान की महिमा – प्रमोद भार्गव....................12

प्रकाश और ज्ञान –सतीश शर्मा.......................15

अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू मंदिर क्यों महत्वपूर्ण हैं? – पंकज जयस्वाल...............16

समर बड़ा भीषण होगा – नरेन्द्र भदौरिया................19

मेरा गांव मेरा परिवार – ललित शंकर........... 21

अर्थव्यवस्था के निज मॉडलों से ही भारत बनेगा... – डॉ. आशीष कुमार............22

विकास की वेदी पर आदिवासी समाज – शुभम यादव.................... 24

मीडिया सुर्खियां – प्रतीक खरे................26

पाठकगण पत्रिका के बारे में अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया,'संपादक के नाम पत्र' शीर्षक से ई-मेल (keshavsamvad@gmail.com) के माध्यम से भेज सकते हैं। चुने हुए पत्रों को पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

संपादकीय

नए युग में भारत प्रवेश कर रहा है। वैश्विक धरातल पर भारत का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है। भारत के महत्व से अर्थ है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय चिंतन का महत्व। वर्तमान विश्व में रहन-सहन और खान-पान के आधुनिक तौर-तरीकों ने मनुष्य के सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संतुलन पर विपरीत प्रभाव डाला है। भारत की प्राकृतिक नियमों पर आधारित जीवन शैली और समाज कल्याण को समर्पित पद्धति विश्व के बौद्धिक वर्ग को आकर्षित कर रही है। भारत के खानपान में क्षेत्रीय जलवायु के अनुरूप विभिन्न खाद्य परंपराएं विकसित हुई है। यही कारण है कि भारत के भोजन की थाली भी विविधतापूर्ण है। भारत के मोटे अनाज की खाद्य परंपरा के लाभ को आज पूरा विश्व स्वीकार रहा है। जिस प्रकार भोजन की विविधता से हमारा शरीर पोषित होता है उसी प्रकार से देश की सांस्कृतिक विविधता से यह राष्ट्र विकसित और पोषित होता आया है। भारत के सदियों प्राचीन पर्व, उत्सव और त्योहारों में ही भारत का स्पंदन होता है, गत दिनों में संपूर्ण राष्ट्र में प्रभु श्रीराम के प्राकट्य दिवस रामनवमी और राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया यह पर्व/उत्सव भारत के जनमानस में राष्ट्रीय संस्कृति का बोध कराने वाले हैं। कुछ स्थानों पर उपद्रवियों ने बाधा भी पहुंचाई, परंतु यह निश्चित है कि भारतीय संस्कृति के नवजागरण पर ऐसे उपद्रवियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सांस्कृतिक उत्थान के साथ-साथ भारत आर्थिक उन्नति के मार्ग पर भी बढ़ रहा है और विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियों में स्थान पाने में सफल हुआ है। यह हम भारतीयों की दृढ़ इच्छाशक्ति का ही प्रतीक है कि कोरोना आपदाकाल को हमने अवसर में बदला। विशेष रूप से ग्रामीण आँचल में रहने वाले हमारे सभी बंधु भगिनी विशेष बधाई के पात्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के स्वदेशी मॉडल पर काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज के ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक धरातल पर अनुभव के माध्यम से अर्जित किए गए ज्ञान का उपयोग कर भारत के युवा नवोन्मेष के माध्यम से भारत के नवनिर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत का युवा भी अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, जैसे-जैसे वह पाता है कि भारत की संस्कृति में वैज्ञानिकता और तर्कयुक्त ज्ञान समाहित है वैसे-वैसे न केवल वह गौरवान्वित होता है अपितु इस ज्ञान को जीवन में धारण भी करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के सांस्कृतिक केंद्रों को इस तरह से विकसित करने पर बल दिया गया है जिससे कि वे आर्थिक स्वावलंबन के केंद्र भी बन सके वह सराहनीय कदम है। हमारे तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं के आवागमन तथा पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के पहुंचने की संख्या में आशातीत वृद्धि देखी गई है जिससे तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से जुड़े हुए लोगों के स्वावलंबन की दिशा में भी अप्रत्यक्ष सफलता मिली है। भारत ने अब यह समझ लिया है कि भारत स्वदेशी परंपराओं तथा भारतीय समाज पर आधारित अर्थव्यवस्था के मॉडल से ही उन्नति और प्रगति का नया अध्याय लिखेगा। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे युवा भारत आधारित स्टार्टअप योजनाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान कर रहे हैं। वर्षों से हाशिए पर रखे गए जनजातीय एवं वंचित समाज के बंधुओं का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन किया जा रहा है और वे भी राष्ट्र की उन्नति में सफल योगदान देने की योग्यता सिद्ध कर रहे हैं। हम सभी का यह स्वप्न है कि हमारा राष्ट्र भारतवर्ष वैभव संपन्न बने, इसके लिए प्रत्येक भारतीय में राष्ट्र-बोध का भाव प्रेरक तत्व है।

संपादक

ISSN No. 2581-3528

स्वस्थ विश्व का आधार बना 'मिलेट्स'

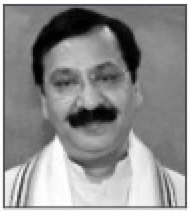

प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी

मिलेट्स यानि मोटा अनाज हमारे स्वास्थ्य, खेतों की मिट्टी, पर्यावरण और आर्थिक समृद्धि में कितना योगदान कर सकता है, इसे इटली के रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय में मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष (आईवाईओएम) के शुभारंभ समारोह के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश से समझा जा सकता है –

'हमारी जमीन और हमारी थाली में विविधता होनी चाहिए। अगर खेती इकहरी फसल वाली हो जाए, तो इसका बुरा असर हमारे और हमारी जमीन के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मोटे अनाज हमारी खेती और हमारे भोजन की विविधता बढ़ाते हैं। 'मोटे अनाजों के प्रति सजगता बढ़ाना' इस आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग और संस्थाएं, दोनों ही बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। संस्थाओं के प्रयास से मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है और समुचित नीतियां अपनाकर इनकी फसल को फायदेमंद बनाया जा सकता है। दूसरी ओर, लोग भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए मोटे अनाजों को अपने आहार में शामिल करके इस पृथ्वी के अनुकूल विकल्प चुन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि 2023 में मोटे अनाजों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का यह आयोजन सुरक्षित, टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक जन आंदोलन को जन्म देगा।'

पिछले कुछ सालों से, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरुकता बढ़ी है, लेकिन खासकर कोरोना के बाद से यह चेतना चिंता में बदल गई है। लोगों ने महसूस किया है कि अगर खानपान और जीवनशैली में बदलाव नहीं लाया गया, तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि ज्वार, रागी, कोदो, सामा, बाजरा, सांवा, कुट्टू, जैसे अनेक मोटे अनाज की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ी है।

2018 में मनाया गया राष्ट्रीय मिलेट वर्ष : लेकिन भारत ने तो इस चेतना की अलख काफी पहले से ही जगानी शुरू कर दी है। 2014 में जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, तभी से इस दिशा में प्रयास किये जाने लगे थे। इन्हीं प्रयासों का नतीजा था वर्ष 2018 को सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया गया। ऐसा करने का उद्देश्य लोगों में मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देना, इनके उत्पादन को प्रोत्साहित करना और इनकी मांग बढ़ाना था। इसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मिलेट के वैश्विक उत्पादन में 18 प्रतिशत भागीदारी के साथ भारत आज विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश बन चुका है और प्रति

हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से भी दुनिया के मिलेट उत्पादक देशों में दूसरे स्थान पर आ चुका है।

बढ़ रहा है उत्पादन और उत्पादकता : वर्तमान में विश्व के लगभग एक सौ तीस देशों में मिलेट उगाये जा रहे हैं और एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले लगभग साठ करोड़ लोगों के नियमित भोजन का हिस्सा बने हुए हैं। उत्पादन और उत्पादकता के 2016 से 2021 के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हम पायेंगे कि विश्व के पांच सबसे बड़े पोषक अनाज (मिलेट) उत्पादक देशों में भारत के अलावा नाइजर, सूडान, नाइजीरिया और माली जैसे देश शामिल हैं। इनमें भारत में 142.93 लाख हेक्टेयर जमीन पर इनकी खेती होती है और पांच सालों में औसतन 156.12 लाख टन मिलेट का उत्पादन हुआ, जबकि दूसरे स्थान पर रहे नाइजर में 107.16 हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ 56.39 लाख टन उत्पादन रहा। पूरे विश्व में मिलेट उत्पादन का औसत 890.92 लाख टन है, जिसमें 156.12 लाख टन से ज्यादा भारत में उपजा है। उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) की दृष्टि से सिर्फ नाइजीरिया ही भारत से आगे है, वह भी बहुत कम। नाइजीरिया में यह उत्पादकता 1103 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और भारत में 1092 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वैश्विक उत्पादकता 1211 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के यह काफी करीब है।

इस सबका श्रेय जाता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति को, जो मिलेट को हमारी रसोईयों में और हमारी प्राथमिकताओं में उसकी खोई जगह वापस दिलाने के लिए कटिबद्ध है। वह जगह, जो पचास साल पहले तक मोटे अनाजों के लिए सुरक्षित हुआ करती थी।

प्राचीन है भारत में मोटे अनाजों की परंपरा : सच तो यह है कि मोटे अनाज हजारों साल से हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहे हैं। खान–पान की हमारी इस समृद्ध विरासत की जड़ें, सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाती हैं। आदिकाल के 'यजुर्वेद', 'सुश्रुत संहिता', कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुंतलम', कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से 'आईना–ए–अकबरी' तक अनेक महान ग्रंथों में मोटे अनाजों के बारे में वर्णन है। इससे पता चलता है कि हमारे खानपान में इनकी उपस्थिति कितना पहले से है। यह उपस्थिति अकारण नहीं है। मिलेट्स हर दृष्टि से सभी के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

मिलेट मे प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम, जिंक, मैग्नेशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन, जैसे खनिजों और कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन आदि काफी उच्च मात्रा में पाये जाते हैं। हम जो भी खाते हैं, उसका अधिकतर हिस्सा हमारे पेट में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर हमारे रक्त में मिल जाता है, जो कि शुगर का एक मृदु रूप होता है। गेंहू व चावल जैसे आधुनिक दौर के लोकप्रिय अनाजों की तुलना में मिलेट इसलिए बेहतर हैं, क्योंकि इनके ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत काफी धीमी होती है। इसके अलावा ये ग्लूटोन मुक्त होने के कारण कई प्रकार के उदर रोगों से भी बचाते हैं। इन सब कारणों से इस वजह से यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माने जाते हैं।

पोषक तत्वों और खनिजों की मौजूदगी के कारण मिलेट फसलों के पुआल को भी पशुओं के चारे के रूप में काफी पोषक माना जाता है। कुपोषण से निपटने के मामले में भी मिलेट उत्कृष्ट विकल्प साबित हुए हैं। भारत में कुछ राज्यों में स्कूलों में मध्यान्ह भोजन में मिलेट से बने आहार को शामिल किया गया, तो इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले और बच्चों के बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला।

पर्यावरण के अनुकूल होते हैं मिलेट : मिलेट पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद उपयोगी हैं। ये विभिन्न प्रकार के तापमानों वाले नम और शुष्क सभी क्षेत्रों में उगाये जा सकते हैं। उन्हें पनपने के लिए पानी और वर्षा की जरूरत कम होती है। ये महज 300–400 मिमी पानी में भी भी उग सकते हैं। ये लगभग हर प्रकार की मिट्टी में अंकुरित हो सकते हैं। इनमें कीड़े लगने की आशंका भी नहीं के बराबर होती है। इसलिए इनमें केमिकल फर्टिलाइजरों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की की बहुत कम जरूरत होती है। मिलेट का फसल चक्र भी बारीक अनाजों की तुलना में बेहतर होता है, क्योंकि अधिकतर मिलेट को परिपक्व होने में 60–90 दिनों की आवश्यकता होती है, जबकि बारीक अनाज के लिए यह अवधि 100 से 140 दिन हो सकती है। मोटे अनाजों की खेती में आने वाला खर्च भी कम होता है। इन सब वजह से मिलेट की खेती, छोटे

किसानों के लिए काफी फायदेमंद हैं।

क्लाइमेट चेंज की चुनौती से जूझती दुनिया के लिए भी मिलेट किसी वरदान से कम नहीं हैं, क्योंकि इनमें कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व पर खाद्यान्नों की कमी का जो संकट मंडरा रहा है, अपनी सहज और सरल उपजता की प्रवृत्ति के कारण मिलेट्स उससे निपटने में भी हमारी काफी सहायता कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मिलेट काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें काफी बड़ा योगदान भारत का भी है। मिलेट के महत्व को फिर से स्थापित करने में जो सफलता हासिल की है, उसने पूरी दुनिया को मोटे अनाजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

प्रयासों से मिले सकारात्मक परिणाम : यह सफलता हमें अनायास ही नहीं मिली है। इसके लिए हमने अथक प्रयास किए हैं। जैसे कि वर्ष 2018–19 में हमने मिलेट को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) से जोड़ा और पोषक इसके उपमिशन के रूप में देश के 212 जिलों में लागू किया। इनमें पोषक अनाज में सोरघम (ज्वार), पर्ल मिलेट (बाजरा), फिंगर मिलेट (रागी/मंडुआ) और कुटकी, कोदो मिलेट(कोदो), बार्नयार्ड मिलेट (सावाध्झंगोरा), फॉक्सटेल मिलेट (कंगनीध्काकुन), प्रोसो मिलेट (चीना) जैसे छोटे मिलेट शामिल हैं। इनके अलावा कुट्टू और चौलाई को भी पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है।

एनएफएसएम–पोषक अनाज के अंतर्गत क्लस्टर क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना, इनके लिए प्रसंस्करण इकाइयों, उत्कृष्टता केंद्रों, बीज केंद्रों का निर्माण, कार्यक्रमों व कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनीकिट वितरण, संचार माध्यमों के जरिये प्रचार तथा प्रगतिशील किसानों, उद्यमियोंध्गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, लोगों में जागरूकता पैदा करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इसके अलावा इस उपमिशन में क्लस्टर फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन (एफएलडी), संकर और उच्च उपज नस्लों के प्रमाणित बीजों का वितरण–उत्पादन, जैव–उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व, पौधों को सुरक्षा देने वाले रसायन और खरपतवारनाशी, मैनुअल स्प्रेयर, स्प्रिंकलर, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत हिसार में बाजरे के लिए सीसीएस हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद में ज्वार के लिए भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान और बेंगलुरु में छोटे मिलेट के लिए कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे तीन राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना भी की गई है।

एनएफएसएम के तहत मिलेट को प्रोत्साहन देने के क्रम में देश के 13 राज्यों में पोषक अनाज के ब्रीडर बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/आईसीएआर संस्थानों में 18 केंद्र स्थापित किए गए। एनएफएसएम के तहत, स्मॉल फार्मर्स एग्री–बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 2018–2021 के दौरान तीन वर्षों में मिलेट पर 50 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाये गये हैं और कुल 42240 किसानों को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में इसी अवधि के दौरान मिलेट/दलहनों के लिए 30 नए किसान उत्पादक संगठन गठित किए गये हैं, जिनसे तीन वर्षों के दौरान कुल 30624 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, देश में पोषक अनाज की उन्नत किस्मों के गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आईसीएआर संस्थानों, एसएयू और केवीके में 25 बीज केंद्रों की स्थापना की गयी है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) में वही प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण विधियां उपयोग की जाती हैं, जो आईसीएआर – भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद द्वारा उपयोग की जाती हैं। इसका उद्देश्य ज्वार के मूल्यवर्द्धित उत्पादों जैसे मल्टी ग्रेन आटा, सूजी, फ्लेक्स, तैयार किए गए उत्पादों (सेंवई और पास्ता), बिस्कुट, इंस्टेंट मिक्स आदि की अच्छी गुणवत्ता विकसित करना है। इसी के अंतर्गत पर्ल मिलेट, फॉक्सटेल, कोदो और प्रोसो मिलेट आदि से बने मिलेट रवा और पफ बाजार में 'ईट्रीट' के रूप में बेचे जाते हैं। इन उत्पादों को प्रोत्साहन दिए जाने से उपभोक्ताओं के बीच मिलेट के बारे में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने में सहायता मिली है और इन्हें मिले व्यापक समर्थन से उद्यमियों में भी इन्हें लेकर काफी रुचि उत्पन्न हुई है। अब वे इन पौष्टिक, सुविधाजनक और स्वादिष्ट मिलेट उत्पादों में अत्याधिक व्यावसायिक संभावनाएं देखने लगे हैं।

मिलेट को बढ़ावा देने के अपने इस अभियान को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए भारत ने इसी क्रम में एक और अति महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया और मार्च 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त, सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व में हमने संयुक्त राष्ट्र के 75वें अधिवेशन में वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' के रूप में मनाये जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023', न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिलेट को वैश्विक स्वीकार्यता दिलाने का एक अभूतपूर्व अवसर है। इसका इस्तेमाल हम, इनके उत्पादन को शिखर पर ले जाने और हमारी खान–पान परंपराओं में मिलेट को नियमित रूप से अपनाने की आदत को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम संक्षेप में कहें कि 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' भविष्य को बचाने के लिए भारत के नेतृत्व में एक सशक्त पहल है, तो अतिशयोक्ति न होगी।

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान, में महानिदेशक के पद पर कार्यरत है।)

ISSN No. 2581-3528

बिहार से बंगाल तक रामनवमी को फिर बनाया गया निशाना

मृत्युंजय दीक्षित

जिस समय देश उल्लास और उत्साह के साथ रामभक्ति के रंग में डूबकर रामनवमी का पर्व मना रहा था उस समय कुछ शरारती तत्व अपने राजनैतिक आकाओं के बल पर हिंसा का तांडव रच रहे थे। रामनवमी के पावन अवसर पर बंगाल से बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र तक जिस प्रकार से चुन–चुन कर रामनवमी झांकियों, यात्राओं और भक्तों पर पथराव तथा हिंसा की गई वह निंदनीय नहीं घृणित है और उससे भी अधिक घृणित है उस हिंसा को सही ठहराने वाले छद्म धर्मनिरपेक्ष लोगों का व्यवहार फिर वो चाहे कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्यों न हों।

रामनवमी को हिन्दुओं पर हमले के रूप में प्रारम्भ हुयी हिंसा महाराष्ट्र के संभाजीनगर से बंगाल के हावड़ा से होती हुई बिहार के पांच जिलों और झारखड के साहिबगंज तक पहुंच गई। भीषण उपद्रव और हिंसा के बाद महाराष्ट्र व गुजरात में तो स्थिति नियंत्रण में आ गई लकिन बिहार के पांच व बंगाल में कई इलाकों में हिंसा लगातार जारी है। बिहार व बंगाल के उपद्रवियों को पता है कि उन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है तथा वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और यही कारण है कि बिहार के दंगाग्रस्त क्षेत्रों से हिन्दुओं के पलायन के हृदय विदारक विडियो वायरल हो रहे हैं।

भारत की राजनीति में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पहले तो सनातन हिंदू समाज के पर्वों व उनकी शोभा यात्राओं को हिंसक उपद्रवी तत्वों की ओर से जानबूझकर निशाना बनाया जाता है और फिर उसके बाद उनके तथाकथित सेकुलर राजनैतिक नेता टीवी चैनलों पर आकर हिंदू समाज और पीड़ित पक्ष को ही दोषी बताकर उपद्रवियों का हौसला बढ़ाते हैं।

आज पूरा बंगाल व बिहार त्रस्त है। दोनों ही राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठ व रोहिंग्याओं की बाढ़ आ गई है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। यही लोग दोनों ही राज्यों में अशांति का सबसे बड़ा कारण हैं। स्थानीय छद्म धर्मनिरपेक्ष दल अपने निहित स्वार्थों के चलते इनको प्रश्रय दे रहे हैं और इनकी अराजक गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं।

बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हरकतों व उनकी बयानबाजी के कारण ही हिंसा भड़की। रामनवमी के पहले वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गईं और फिर बयान दिया कि वह रामनवमी की शोभायात्रा को रोकेंगी नहीं लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई उपद्रव या हिंसा होती है तो वह बख्शेंगी भी नहीं। माना जा रहा है कि उनके बयानों के कारण ही उपद्रवियो का हौसला बढ़ गया। हावड़ा व अन्य जगहों पर हिंदू समाज को रामनवमी

मनाने से रोकने और डराने–धमकाने के लिए पत्थरबाजी की गई और बम फेंके गये। वाहनों, दुकानों को आग लगाई गई और जमकर लूटपाट की गई। बंगाल के वर्धमान जिले में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। आज पूरा बंगाल जल रहा है।

आजकल हिंदू विरोधियों और उनके आकाओं ने हिंसा और उसके बाद के भाषणों का एक नया पैटर्न बना लिया है। पहले उपद्रवी पत्थरबाजी, हमले और हिंसा करते हैं और उसके बाद उनके आका बयां जारी करते हैं कि शोभायात्रा में शामिल लोग जोर –जोर से डीजे बजा रहे थे या फिर वो मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाकों से क्यों निकले या फिर किसी मस्जिद के सामने नारे क्यों लगाए? यह राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि का एक खतरनाक पैटर्न है। बंगाल के हावड़ा तथा अन्य जिलों में हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू समाज पर ही आरोप मढ़ रही हैं और और अंतिम जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही जज बन गयी हैं।

बंगाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजमूदार को हावड़ा का दौरा नहीं करने दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दंगों की जांच एनआईए व सीबीआई से कराने के लिए के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जबकि गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से पूरी रिपोर्ट तलब की है जिसके लिए प्रदेश के राज्यपाल बंगाल के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री हर दंगे के बाद यही दावा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही बंगाल को बदनाम करने के लिए बाहर के लोगों को बुलाकर दंगा कराती है और ये भूल जाती हैं कि प्रदेश में दंगा न होने पाए इसकी जिम्मेदारी खुद उनके ऊपर है, जनता उनके इस गैर जिम्मेदार व्यवहार को देख रही है।

कुछ दिन पूर्व आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह की बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी जो घोटालों व कर्ज के जाल में गले तक फंसीं प्रधानमंत्री पद की दावेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छी नहीं लगी और उसके बाद से ही वह ऐसी बयानबाजी करने लगीं जिसका परिणाम रामनवमी पर हिंसा व उपद्रव के रूप में सामने आया। यह वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो उप्र के हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक घटना का राजनैतिक लाभ लेने के लिए हाथरस जाना चाह रही थीं, टीएमसी के सांसद भी हाथरस आने के लिए खूब हंगामा मचा रहे थे और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे लेकिन जब उनके अपने राज्य बंगाल में हालात दयनीय हैं तब वह और उनका प्रशासन भाजपा नेताओं ही नहीं वरन स्वयं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि राज्यपाल को हावड़ा सहित हिंसा प्रभावित क्षेत्रों मे जाने से रोक रहा है।

बिहार की स्थिति भी बंगाल से बहुत अलग नहीं है। रामनवमी के पावन अवसर पर बिहार के बिहार शरीफ सहित पांच जिलों में हिंसा का तांडव हो रहा है। हिंसा का पैटर्न बंगाल जैसा ही है और स्थितियां अत्यंत दयनीय हो चुकी हैं। बिहार शरीफ वहीं जिला है जहां विगत दिनों भारत को 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ था। बिहार के उपद्रव ग्रस्त जिलों में हालात इतने अधिक बदतर हैं कि पुलिस की जबर्दस्त मुस्तैदी के बाद भी बमबाजी हो रही है व गोलियां चल रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे पर प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से बातचीत की है और भारी संख्या में अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियां भेजने का ऐलान किया हैं जिसमें कुछ पहुंच भी गई है। बिहार में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति और अर्धसैनिक बलों का पहुंचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है और अब इन सभी लोगों ने दंगाईयों की जगह भाजपा पर हमला बोल दिया है। बिहार की हिंसा पर जदयू के एक नेता का बयान आया कि वह बिहार को गुजरात नहीं बनने देंगे? जबकि राजद नेता का बयान आया कि हिंसा, घृणा और नफरत की राजनीति केवल बीजेपी का ही काम है। दंगों में अपना सब कुछ गंवाने वाला हिंदू समाज इससे हतप्रभ है।

बंगाल से बिहार तक रामनवमी पर जो हिंसा हो रही है वह न केवल हिंदू वरन् भारत विरोधी टूलकिट का ही अंग है। बिहार से बंगाल तक की यह हिंसा पूरी तरह सुनियोजित है जिसे बंगाल और बिहार के सत्ताधारी दलों का समर्थन प्राप्त है। यह प्रायोजित हिंसा उस समय की जा रही है जब भारत जी 20 की अध्यक्षता कर रहा है। इन प्रायोजित दंगों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को संपूर्ण विश्व में खराब किये जाने की चेष्टा हो रही है।

हिंदू समाज के सभी पर्व उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता के पर्याय हैं, उनकी शोभायात्राएं उमंग से भरी हुई होती हैं और उनमें गीत संगीत एक स्वाभाविक गुण की तरह होता है। वे गाते बजाते चलते हैं किसी पर पत्थर मारते हुए नहीं चलते। देश का नागरिक होने के नाते वे प्रशासन से अनुमति लेकर जहाँ से चाहे निकल सकते हैं फिर वो कौन लोग हैं जो घात लगाकर उनपर हमला करते हैं? हिंदू समाज के पर्वो को अशांत करना, पर्व मना रहे लोगों पर हमला करना बिना सुनियोजित साजिश के संभव नहीं है।

अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले दलों का यह दोहरा राजनैतिक चरित्र नहीं तो और क्या है ? ये सभी पार्टियां और नेता हिंदू समाज के प्रति नफरत और घृणा का जहर बोकर उन्हें अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना पालने वाले तथाकथित सेकुलर लोग भारत को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं। भारत के सभी सेकुलर दल वास्तव में घोर हिंदू विरोधी हैं।

हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यदि धर्म के नाम पर विभाजित किये जाने के बाद भी आज भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो केवल इसलिए कि हिन्दू समाज अभी भी कुछ सीमा तक बहुसंख्यक है। हिंदू समाज के लोग कभी भी किसी अन्य मतावलंबी का अहित नहीं चाहते और यह विश्व का सर्वाधिक सहिष्णु समाज है।

(लेखक स्तम्भकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

आर्थिक प्रगति में शुचितापूर्ण नीतियों का अपनाया जाना जरूरी

प्रहलाद सबनानी

हाल ही के समय में भारत के आर्थिक विकास की दर में बहुत तेजी आती दिखाई दे रही है एवं आगे आने वाले समय में आर्थिक प्रगति की गति और अधिक तेज होने की उम्मीद की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के अपने लाभ भी हैं और नुक्सान भी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करते समय इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है कि इस संदर्भ में प्रगति के लिए जो नीतियां अपनायी जा रही हैं वे जनता की अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। साथ ही, देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए गलत आर्थिक नीतियों को लागू नहीं किया जाय क्योंकि गलत आर्थिक नीतियों को अपनाते हुए आर्थिक स्त्रोतों को बढ़ाना देश एवं जनता के हित में नहीं होता है। आर्थिक प्रगति के इस खंडकाल में इस बात पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है कि भारत की आर्थिक प्रगति में शुचितापूर्ण नीतियों का पालन किया जा रहा है। आर्थिक प्रगति किसी भी कीमत पर हो एवं चाहे इसके लिए भविष्य में देश के नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़े, इसे भारतीय संस्कार मंजूर नहीं करते हैं। भारत को परम वैभव के स्तर पर ले जाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना ही हितकर होगा। विश्व के अन्य कई देशों में जब आर्थिक विकास की गति तेज हुई है एवं इन देशों ने विकसित देशों की श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया है, इस दौरान इन देशों में कई प्रकार की नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं गलत आर्थिक नीतियों को अपनाने के कारण पनपी हैं, जिनका हल ये देश आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए भारत को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करते समय अभी से सतर्क रहना जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याएं भारत में निर्मित ही न हो।

आज अमेरिका, यूरोप एवं अन्य कई देश विभिन्न प्रकार की आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं एवं इन समस्याओं को हल करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। दरअसल विकास का जो मॉडल इन देशों ने अपनाया हुआ है, इस मॉडल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे कई छिद्रों को भर नहीं पाने के कारण इन देशों में कई प्रकार की समस्याएं बद से बदतर होती जा रही हैं। जैसे नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में लगातार ह्रास होते जाना, सुख एवं शांति का अभाव होते जाना, इन देशों में निवास कर रहे लोगों में हिंसा की प्रवृति विकसित होना एवं मानसिक रोगों का फैलना, मुद्रा स्फीति, आय की बढ़ती असमानता, बेरोजगारी, ऋण का बढ़ता बोझ, घाटे की वित्त व्यवस्था, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण होना, ऊर्जा का संकट पैदा होना, वनों के क्षेत्र में तेजी से कमी होना, प्रतिवर्ष जंगलों में आग का लगना, भूजल का स्तर तेजी से नीचे की ओर चले जाना, जलवायु एवं वर्षा के स्वरूप में लगातार परिवर्तन होते रहना, आदि। इन सभी समस्याओं के मूल में विकसित देशों द्वारा आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए पूंजीवादी मॉडल को माना जा रहा है।

वैसे तो पूंजीवादी मॉडल में कई प्रकार की कमियां दिखाई देने लगी हैं परंतु हाल ही के समय की एक ज्वलंत आर्थिक समस्या का वर्णन करना यहां उचित होगा। विशेष रूप से कोरोना महामारी के कालखंड के पश्चात एवं रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति कड़ियों में उत्पन्न हुई समस्याओं के चलते विश्व के लगभग सभी देश मुद्रा स्फीति की गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। लगभग सभी देश, पूंजीवादी मॉडल के अनुसार, ब्याज दरों में लगातार वृद्धि कर उत्पादों की मांग बाजार में कम करते हुए मुद्रा स्फीति की समस्या से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु, पिछले एक वर्ष से लगातार किए जा रहे इस प्रयास से मुद्रा स्फीति की समस्या से छुटकारा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्याज दर के लगातार बढ़ाते जाने से कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति तो नियंत्रण में नहीं आ पा रही है परंतु अन्य कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं जरूर उभर रही हैं। जैसे, कम्पनियों के व्यवसाय में कमी होना, लाभप्रदता में कमी होना, कर्मचारियों की छंटनी होना, करों के संग्रहण में कमी होना एवं बेरोजगारी का बढ़ना, देश की विकास दर में कमी आना, आदि। इस कारण से अब यह सोचा जाना चाहिए कि इन परिस्थितियों में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का बढ़ाते जाना क्या सही उपाय है। इस तरह के उपाय पूर्व में विकसित अर्थव्यवस्थाओं, जिन्होंने पूंजीवादी मॉडल के अनुसार अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, द्वारा किए जाते रहे हैं। जबकि, अब यह उपाय बोथरे साबित हो रहे हैं। मुद्रा स्फीति के लगातार बढ़ते जाने के बीच विकसित देशों में कई कम्पनियों ने अपने ही

ISSN No. 2581-3528

कर्मचारियों की छंटनी जैसे अमानवीय निर्णय लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई है और 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की छंटनी इन कम्पनियों द्वारा की जा रही है।

इसी प्रकार, विश्व में आज ऐसे कई देश हैं जिनके 20 प्रतिशत नागरिकों के पास देश की 80 प्रतिशत से अधिक सम्पत्ति जमा हो गई है। जबकि 80 प्रतिशत नागरिकों के पास देश की केवल 20 प्रतिशत से भी कम संपत्ति है। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उत्पादों पर कितना लाभ लेती हैं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इन कारणों के चलते ही आज विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के साथ साथ अमीर व्यक्ति अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब होता जा रहा है। आज अमेरिका जैसे विश्व के सबसे अमीर देश में भी लगभग 6 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वे खुले में रहने को मजबूर हैं। आय की असमानता के रूप में यही हाल लगभग सभी विकसित देशों का है। अमेरिका की कुल आबादी के 11.4 प्रतिशत नागरिक, जापान में 15.7 प्रतिशत नागरिक एवं जर्मनी में 15.5 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग यही स्थिति अन्य विकसित देशों की भी है।

इसके ठीक विपरीत, भारत के बहुत पुराने समय के इतिहास में महंगाई नामक शब्द का वर्णन ही नहीं मिलता है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता था एवं वस्तुओं की आपूर्ति सदैव ही सुनिश्चित रखी जाती थी अतः मांग एवं आपूर्ति में असंतुलन पैदा ही नहीं होने दिया जाता था। भारत ने भी हाल ही में हालांकि ब्याज दरों में वृद्धि की है परंतु विशेष रूप से कृषि उत्पादों की आपूर्ति पर विशेष ध्यान देते हुए महंगाई को तुलनात्मक रूप से नियंत्रण में बनाए रखा है। इसी प्रकार, अन्य विकसित देशों द्वारा भी लगातार ब्याज दरों में वृद्धि करने के स्थान पर उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाकर मुद्रा स्फीति का हल निकाला जाना चाहिए। विशेष रूप से मुद्रा स्फीति की समस्या उत्पन्न ही इसलिए होती है कि सिस्टम में उत्पादों की मांग की तुलना में आपूर्ति कम होने लगती है। कोरोना महामारी के दौरान एवं उसके बाद रूस एवं यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों में कई उत्पादों की आपूर्ति बाधित हुई है। जिसके कारण मुद्रा स्फीति इन देशों में फैली है।

दरअसल पश्चिमी दर्शन भौतिकता प्रधान है और वहां व्यक्ति ही प्रधान है इसलिए वहां असीम उपभोगवाद है। अतः पश्चिमी व्यक्ति तात्कालिक शारीरिक सुख को ही प्रधानता देता है। शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए वह मानता है कि उसके लिए कुछ भी करना उचित है, चाहे वह जायज हो अथवा नाजायज। इसके कारण पश्चिम में अर्थ रचना ऐसी है कि जिसके माध्यम से सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीब वर्ग को लाभ हो अथवा न हो परंतु कुछ व्यक्तियों, वर्गों अथवा समुदायों को समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं जरूर मिलती है, उनकी पूंजी बढ़ती है, उनका मुनाफा बढ़ता है। पश्चिमी संस्कृति एवं उनके दर्शन का अर्थशास्त्र पर परिणाम यह होता है कि व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत लाभ के कारण पश्चिमी लोगों में शोषण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे पश्चिम की सारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

पश्चिमी दर्शन के ठीक विपरीत भारतीय दर्शन में सम्पूर्ण अस्तित्व, ब्रह्मांड या विश्व को एकात्म भाव से देखने का वर्णन है। प्राचीन भारत में अर्थ रचना ऐसी रही है जिससे देश के सभी नागरिक सम्पन्न एवं सुखी रहे हैं। भारतीय शास्त्रों में संयमित उपभोग की बात कही गई है। भारत में प्राणी तथा वनस्पति का विचार भी आत्मीयता के साथ किया जाता रहा है। भारत में सर्वसाधारण सोचता रहा है कि अर्थ अर्थात सम्पत्ति का विचार सभी मानवों के लिए समान है। भारतीय परम्परा में यह विचार भी है कि देश में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी सुविधाएं हैं, यह सब कुल मिलाकर देश की सम्पत्ति, 'अर्थ' है। भारत में इन विचारों को व्यावहारिक स्तर पर लागू किया जाता रहा है।

परंतु, वर्तमान में भारत में भी आर्थिक दृष्टि से कुछ कमियां तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जिन्हें ठीक करना नितांत आवश्यक है। भारत में निचले स्तर की 20 प्रतिशत जनसंख्या की आय देश की कुल आय का 5 प्रतिशत है जबकि ऊपरी स्तर के 20 प्रतिशत जनसंख्या की आय देश की कुल आय का लगभग 50 प्रतिशत है। भारत में जनवरी 2023 में बेरोजगारी की दर 7.14 प्रतिशत थी, जबकि आदर्श स्थिति में यह शून्य के स्तर पर होनी चाहिए। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2019 में 10.2 प्रतिशत थी। भारत में प्रति व्यक्ति आय अन्य कई देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रत्येक भारतीय की औसत आय 2,200 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है जबकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति औसत आय 70,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है और चीनी नागरिक की औसत आय 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है।

भारत में अर्थ से सम्बंधित प्राचीन ग्रंथों, आध्यात्मिक ग्रंथों सहित, में यह भी कहा गया है कि यह राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की अर्थ से सम्बंधित समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करे। पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा है कि किसी भी राजनैतिक दल के लिए केवल राजनैतिक सत्ता हासिल करना अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि यह एक माध्यम बनना चाहिए इस बात के लिए कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके। श्री उपाध्याय ने इस संदर्भ में एक मॉडल भी दिया है जिसे उन्होंने "एकात्म मानववाद" का नाम दिया है। इस मॉडल के क्रियान्वयन से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास होगा। उसका सर्वांगीण उदय होगा। उक्त मॉडल को साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद या साम्राज्यवाद आदि से हटाकर राष्ट्रवाद का धरातल दिया गया है। भारत का राष्ट्रवाद विश्व कल्याणकारी है क्योंकि उसने "वसुधैव कुटुम्बकम" की संकल्पना के आधार पर "सर्वे भवन्तु सुखिनः" को ही अपना अंतिम लक्ष्य माना है। यही हम सभी भारतीयों का लक्ष्य बनना चाहिए।

इस प्रकार भारत को अपनी आर्थिक तरक्की के समय पश्चिमी दर्शन के स्थान पर भारतीय दर्शन को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि पश्चिमी देशों में उत्पन्न हुई नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से आर्थिक विकास के शुरूआती दौर में ही बचा जा सके।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक पद से सेवा निवृत्त हैं)

ISSN No. 2581-3528

डिग्रियों पर विवाद और ज्ञान की महिमा

प्रमोद भार्गव

अकसर तर्क अंहकार को जन्म देता है, जो अपरिपक्व ज्ञान पर आधारित होता है। हमारे देश में प्रमाण–पत्र और उपाधि (डिग्री) आधारित शिक्षा यही कर रही है। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन शालेय शिक्षा कुशल–अकुशल की परिभाषाओं से ज्ञान को रेखांकित किए जाने के कारण महज कागजी काम से जुड़े डिग्रीधारी को ही ज्ञान का अधिकारी मान लिया है। जबकि परंपरा अथवा काम के प्रति श्रमसाध्य समर्पण के बूते कौशल–दक्षता हासिल कर लेने वाले राजनेता, समाजसेवी, फिल्म, टीवी व लोक कलाकार, शिल्पकार मारवाड़ी व्यापारी और किसान को अशिक्षित व अज्ञानी माना जाता है। डिग्री बनाम योग्यता जैसे विवादास्पद मुद्दे से जुड़े ऐसे मामले हाल ही में महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में सामने आए हैं। इसी समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 23 फर्जी विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची जारी की है। क्या हम इन संस्थानों से अपेक्षा रख सकते हैं कि उनका डिग्री बांटने का आधार योग्यता रहा होगा? जिन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्तम शिक्षा देने के लिए खड़ा किया गया था, उनमें से बीते पांच साल के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के 19 हजार से ज्यादा छात्र बीच में ही संस्थान छोड़ गए। केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने हाल ही में राज्यसभा में यह जानकारी दी है। जिस देश में उच्च शिक्षा के ऐसे बदतर हाल हों, वहां के सत्ता के कर्णधार उन लोगों की डिग्रियों पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं, जो देश–दुनिया में अपनी महानता के बहुआयाम स्थापित कर चुके हैं। इसे उच्च डिग्रीधारियों की सोच की विडंबना ही कहा जाएगा।

सफल टीवी कलाकार व राजनेत्री स्मृति ईरानी के संदर्भ में भी इस सवाल ने उस समय तूल पकड़ा था, जब मात्र बारहवीं कक्षा पास होने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने उन्हें शिक्षा की सभी संभावनाओं से संबद्ध मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया था। उच्च शिक्षा से लेकर सभी भारतीय तकनीकी संस्थान इसी मंत्रालय के अधीन हैं। इसलिए सवाल उठाया गया था कि जो व्यक्ति खुद इंटर तक पढ़ा है, वह शिक्षा के उच्चतम मानकों को कैसे समझेगा? इस सोच में डिग्री आधारित आभिजात्यवादी मानसिकता रही थी। आधुनिक व अंग्रेजी शिक्षा की इस देन ने हमारे मस्तिष्क के दायरे को संकीर्ण किया है। इससे उबरे बिना कल्पनाशील प्रतिभाओं को उनकी मेधा के अनुरूप स्थान मिलना मुश्किल है। अब यह मुद्दा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उठाए सवालों पर गर्माया हुआ है। सिन्हा ने आईटीएम ग्वालियर में डॉ राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यानमाला में अकारण महात्मा गांधी शैक्षिक योग्यता पर बात करते हुए कहा कि 'उनके पास एक भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी। उनके पास केवल हाई स्कूल का डिप्लोमा था। उन्होंने वकालत करने के लिए अहर्ता प्राप्त की थी, कोई कानूनी डिग्री उनके पास नहीं थी।'

हालांकि देश और दुनिया ने उनका लोहा किसी कथित डिग्री से नहीं आजादी के संघर्ष और सत्य व अहिंसा के सिद्धांत से माना। इस सिद्धांत के आदर्श किसी पाठ्यक्रम की किताब से नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन के मूल से उन्होंने आत्मसात किए थे। 'गीता' उनकी प्रेरणा की मुख्य आधार रही है। तत्पश्चात भी गांधी के परपोते तुषार गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि 'उन्होंने 10 वीं की परीक्षा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से उत्तीर्ण की थी। लंदन से भी दसवीं परीक्षा के समकक्ष मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की थी। यही नहीं लंदन विश्वविद्यालय से संबद्ध इनर टेंपल विधि महाविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा उन्होंने लातिन और फ्रेंच में दो डिप्लोमा

हासिल किए थे।' यानी या तो एमटेक होने के बावजूद सिन्हा का ज्ञान अधूरा है या वे पूर्वग्रही मानसिकता से ग्रस्त हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया। तब भी उन्होंने एक बार फिर मोदी की शैक्षिक योग्यता पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि 'आज देश के सामने एक ही प्रश्न है कि क्या इक्कीसवीं सदी में देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होना चाहिए या नहीं? यदि पीएम पढ़े होंगे तो कोई बहलाकर कहीं भी उनसे हस्ताक्षर नहीं करा पाएगा।' केजरीवाल वही मुख्यमंत्री हैं, जिनके सरकार के शिक्षा मंत्री शराब नीति घोटाले में और सत्येंद्र जैन मनी लांड्रिंग के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। इस सिलसिले में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ठीक ही कहा है कि सत्येंद्र और मनीष से तो दस्तखत किए जाएंगे, लेकिन केजरीवाल खुद केवल पढ़ेंगे और भ्रष्टाचार कराएंगे, ताकि कोई दूसरा निपटे। 'खैर इस लेखक का उद्देश्य डिग्री से योग्यता की तुलना करना नहीं है, बल्कि जन्मजात योग्यता का मूल्यांकन करना है।

कुछ दिन पहले खबर आई थी कि मंगलुरू के किसान गणपति भट्ट ने नारियल और सुपारी के पेड़ों पर चढ़ने वाली बाइक बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह द्वारिका प्रसाद चौरसिया नाम के एक युवक ने पानी पर चलने के लिए जूते बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के इस युवक की इस खोज के पीछे की कहानी थी कि उसने सुन रखा था, साधु संत साधना के बाद पानी पर चल सकते हैं। द्वारिका ने तप का आडंबर तो नहीं किया, लेकिन अपनी कल्पनाओं को पंख देकर एक ऐसा जूता बनाने की जुगाड़ में जुट गया, जो पानी पर चल सके। इस तकनीक को इजाद करने में वह सफल भी हुआ और पानी पर चलने वाले एक जोड़ी जूतों का आविष्कार कर लिया। इन दोनों खोजों को 'नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन' ने मान्यता भी दी है। इस प्रतिष्ठान के प्रोफेसर अनिल गुप्ता और उनकी टीम देश में मौजूद ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, जो कम मूल्य के ज्यादा उपयोगी उपकरण बनाने में दक्ष हैं। इस अनूठी खोज यात्रा के जरिए यह दल देश भर में 25 हजार ऐसे आविष्कार खोज चुके हैं, जो गरीब लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। इसके पहले विश्व प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिका भी ऐसे 7 भारतीयों की सूची जारी कर चुकी है, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि और मामूली पढ़े–लिखे होने के बावजूद ऐसी नवाचारी तकनीकें इजाद की हैं, जो समूचे देश में लोगों के जीवन में आर्थिक स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं। लेकिन डिग्री को ज्ञान का आधार मानने वाली हमारी सरकारें ऐसी जकड़बंदी में रही हैं कि वह इन अनूठी खोजों को आविष्कार ही नहीं मानती, क्योंकि इन लोगों ने अकादमिक अर्थात् डिग्रीधारी शिक्षा प्राप्त नही की है।

डिग्री ही योग्यता की गारंटी हो, यह ज्ञान को मापने का पैमाना ही गलत है। देश में ऐसे बहुत से पीएचडी और डिलीट हैं, जो प्राथमिक–माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरी पाने में असफल रहे, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोचिंग संस्थाएं खोलकर लाखों चिकित्सक व अभियंता बना दिए। दूसरी तरफ हमारे यहां उच्च तकनीकी शिक्षा के ऐसे भी संस्थान हैं, जो बतौर लाखों रुपए कैपिटेशन फीस, मसलन अनियमित प्रवेश शुल्क लेकर हर साल हजारों डॉक्टर–इंजीनियर बनाने में लगे हैं। इनकी योग्यता को किस पैमाने से नापा जाए ? मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) का घोटाला सामने आया है। इसके माध्यम से हजारों लोग रिश्वत के बूते डॉक्टर,

ISSN No. 2581-3528

इंजीनियर और पुलिस निरीक्षक बन गए। इस घोटाले में भारतीय प्रशासनिक व पुलिस सेवा के उच्च अधिकारी व उनकी संतानों पर भी मामले दर्ज हुए हैं। इनमें कई तो ऐसे हैं जो डिग्रियां लेकर सरकारी नौकरी में भी आ गए थे। रिश्वत के बूते हासिल इस योग्यता को किस कसौटी पर परखा जाए ?

योग्यता को डिग्री से जोड़कर परखने की यह अभिजात्यवादी सोच ऐसे लोगों की है, जो अपनी संतानों के लिए अनियमित प्रवेश के सभी स्त्रोत खुले रखना चाहते हैं। भारत में सोच की यह मानसिकता कोई नई नहीं है, वर्ण और जाति के आधार पर सनातन चली आ रही है। पुरातन युग में जब भी जाति व वर्ण विशेष व्यक्ति की योग्यता उभरी, तब–तब उसे या तो शंबूक की तरह मार दिया गया या एकलव्य की तरह अंगूठा दक्षिणा में ले लिया गया। महाभारत के सूतपुत्र कर्ण दान में अग्रणी होने के साथ धनुर्विद्या में भी दक्ष थे, लेकिन द्रोपदी– स्वयंवर में यही कर्ण जब मछली की आंख भेदने को धनुष उठाने को तत्पर हुए तो कृष्ण तुरंत ताड़ गए कि कर्ण लक्ष्य साधने में सफल होंगे और फिर कृष्ण के संकेत पर द्रोपदी ने कर्ण से सूतपुत्र होने के कारण विवाह न करने की इच्छा जताकर कर्ण को लक्ष्यभेद करने से रोक दिया। तय है, सत्ता–तंत्र से जुड़े सक्षमों के लिए वास्तविक योग्यता को नकारने के उपाय हमेशा होते रहे हैं।

डिग्रीधारी शिक्षा का षड्यंत्र इसलिए भी रचा गया, जिससे परंपरा से ज्ञान हासिल करने वाले लोग सरकारी नौकरियों से वंचित बने रहें। आज फिल्म और टीवी से जुड़े ज्यादातर कलाकारों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है, लेकिन कलाकार श्रेष्ठतम हैं। यदि फिल्म में अभिनय को अकादमिक शिक्षा की बाध्यता से जोड़ दिया जाए तो सिनेमा जगत से उत्कृष्ट कला का वैसे ही लोप हो जाएगा, जैसे शिक्षा से गुणवत्ता का लोप हो गया है। हमारे प्रसिद्ध लोक गायक और खिलाड़ी भी उच्च शिक्षित नहीं हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह, के. कामराज और बीजू पटनायक भी पढ़े–लिखे नहीं थे। अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके रचनाकर्म पर विवि उपाधियां दे रहे हैं। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं,लेकिन अपने–अपने क्षेत्रों में उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं।

दरअसल, आधुनिक शिक्षा और शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की मौलिक कल्पनाशीलता को कुंद करने का काम किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक और दुनिया के प्रमुख अमीर बिल

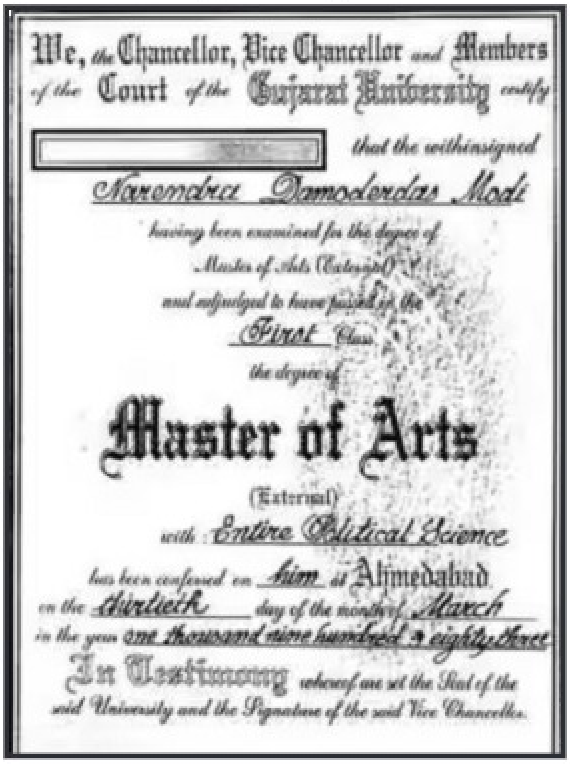
We, the Chancellor, Vice Chancellor and Members of the Court of the Gujarat University certify that the withinsigned

Narendra Damodardas Modi

having been examined for the degree of Master of Arts (External) and adjudged to have passed in the First Class the degree of

Master of Arts

(External)

with Entire Political Science

has been conferred on him at Ahmedabad on the thirtieth day of the month of March in the year one thousand nine hundred & eighty three

In Testimony whereof we set the Seal of the said University and the Signature of the said Vice Chancellor.

गेट्स गणित में बेहद कमजोर थे और इस विषय में दक्षता हासिल करने की बजाय गैराज में अकेले बैठे रहकर कुछ नया सोचा करते थे। तब उनके पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन विलक्षण सोच थी, जिसने कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धि के रूप में माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया। यदि बिल गणित में उच्च शिक्षा हासिल करने में अपनी मेधा को खफा देते तो सॉफ्टवेयर की कल्पना मुश्किल थी।मदन मोहन मालवीय ने जब काशी हिंदू विवि को स्थापित किया तब उन्होंने विषय विशेषज्ञों को ही संस्थान का प्राध्यापक और रीडर बनाया था। रामचंद्र शुक्ल (इंटर), श्यामसुंदर दास (बीए) आयोध्या सिंह उपध्याय हरिऔध (मिडिल) थे, लेकिन इनके योग्यता के आधार पर इन्हें विभाग प्रमुख बनाया गया था। इसी तरह स्नातक नहीं होने के बावजूद देवेंद्र सत्यार्थी को प्रकाशन विभाग की पत्रिका 'आजकल' का संपादक बनाया गया था। प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी महज दसवीं तक पढ़े थे, लेकिन उनकी असाधारण योग्यता के बूते इंडियन एक्सप्रेस समूह के मालिक रामनाथ गोयनका ने उन्हें 'जनसत्ता' का संस्थापक संपादक और 'इंडियन एक्सप्रेस' का संपादक बनाया था। प्रसिद्ध लेखक आरके नारायण दसवीं कक्षा में अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन कालांतर में यही आरके नारायण अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक बने। डॉ राधाकृष्णन ने कहा है कि नौकरियों में उपाधि को महत्व नहीं देकर विषय की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विषय में पारंगत है तो उसे नौकरी में लेना चाहिए। लेकिन नौकरशाही ने इन विद्वानों के कथनों और प्रयोगों को नकार कर मैकाले की डिग्री आधारित पद्धति को आजादी के बाद भी बनाए रखा। जाहिर है, संकल्प के धनी और परिश्रमी लोग औपचारिक शिक्षा के बिना भी अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं।

उपाधि पढ़ाई–लिखाई निर्धारित संकायों का प्रमाण जरुर होती हैं, किंतु वह व्यक्ति की समग्र प्रतिभा,अंतर्दृष्टि और बहुआयामी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकती ? अतएव महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की डिग्री आधारित योग्यता पर सवाल उठाने वाले बड़े डिग्रीधारी अपनी योग्यता का केवल दंभ भर रहे हैं। कम शिक्षित होने के नाते जन्मजात प्रतिभा को नकारना वास्तविक योग्यता के अनादर के अलावा कुछ नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं)

ISSN No. 2581-3528

प्रकाश और ज्ञान

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः।।

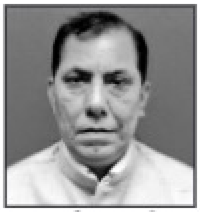

सतीश शर्मा

शास्त्रोक्त पदार्थों को समझने का नाम ज्ञान है और शास्त्र से समझे हुए भावों को वैसे ही अपने अन्तःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम विज्ञान है ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिसका अन्तःकरण तृप्त है अर्थात् जिसके अन्तःकरण में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि बस अब कुछ भी जानना बाकी नहीं है ऐसा जो ज्ञानविज्ञान से तृप्त हुए अन्तःकरण वाला है तथा जो कूटस्थ यानी अविचल और जितेन्द्रिय हो जाता है वह युक्त यानी समाहित कहा जाता है। वह योगी मिट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला होता है।

प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है प्रकाश का अर्थ है इंद्रियां और अंत करण में जागृति। इसका अर्थ है की रजोगुण से होने वाला मनो राज्य तथा तमोगुण से होने वाले निंद्रा–आलस्य और प्रमाद न होकर मन का स्वच्छ होना प्रकाश है। ज्ञान का अर्थ है विवेक यानी कि सत्य–असत्य, कर्तव्य–अकर्तव्य आदि का ज्ञान होना। प्रकाश और ज्ञान आने पर जो लोग उन्हें अपना गुण मानकर अभिमान करते हैं वो वस्तव में अज्ञान या अहंकार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जबकि उन्हें चाहिए कि इन गुणों को प्रभु का आशीर्वाद मान कर भजन ध्यान आदि में लग जाए कारण कि ऐसे समय में किए गए साधन से अधिक लाभ हो सकता है। जब रजोगुण बढ़ता है तब हम पर लोभ–लाभ कमाना और सांसारिक प्रवृत्ति आदि की तरफ बढ़ते हैं। अतः ऐसे समय में हमें यह विचार करना चाहिए कि इस संसार में अपना कुछ भी नही है। रिश्ते नाते और भौतिक वस्तु भी अपनी नहीं है जब सब कुछ मिलने बिछड़ने वाला हैं फिर हमें अपने लिए क्या चाहिए ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। उनसे उदासीन हो जाएं। रजोगुण ध्यान व आत्मशांति का विरोधी है। मनुष्य क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर ही योगारूड हो पाता है। परंतु किया और पदार्थों का संग होने के कारण रजोगुण मनुष्य के सत्व गुण बढ़ने नहीं देते।

यह ज्ञान और प्रकाश हमें बताते हैं कि गुणों से अपना कोई संबंध नहीं है गुण तथा गुणों के कार्य प्रकृति के कार्य हैं और यह परिवर्तनशील है। स्वयं परमात्मा का अंश होने से आत्मा अपरिवर्तनशील है परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है। संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली मिलने बिछुडने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति बनी रहे दुखदाई परिस्थिति न आए, परन्तु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदाई परिस्थिति आती ही है। यह प्रकृति का नियम है। अतः हम सबको प्रत्येक परिस्थिति सहज व सरल रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लगातार बदलते संसार मे अपनापन देखना भूल है। इस भूल के कारण ही हमें तनाव होता है और हम अशांत रहते हैं। देखने में चारों तरफ भौतिक जगत नजर आता है पर वास्तव में ये नाशवान है और नाशवान के साथ सुख कैसा।

(लेखक केशव भाग, नोएडा के संघचालक हैं)

अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू मंदिर क्यों महत्वपूर्ण हैं?

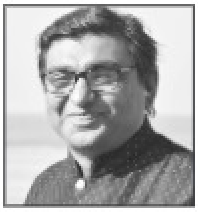

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

भारत में मंदिर देश की समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाते हैं। भारत 2 मिलियन से अधिक मंदिरों का देश है, जिनमें से कई को अत्यधिक आस्था और चमत्कार का स्थान माना जाता है, जो दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करते हैं। हम भारतीय आधुनिकता के इस युग में अपनी संस्कृति, रीति–रिवाजों और धर्म को संरक्षित करना और अपनाना जानते हैं।

प्राचीन काल से ही मंदिर वाणिज्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक जीवन के केंद्र रहे हैं। स्थानीय मंदिर समुदाय का केंद्र था। यह वह जगह है जहां लोगों ने देवी–देवताओं से स्वास्थ्य, धन, संतान, एक विशिष्ट बाधा को दूर करने, या यहां तक कि किसी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। यहीं लोग मिलते थे, समाचारों और विचारों का आदान–प्रदान करते थे, अपनी कहानियाँ, अपनी कठिनाइयाँ साझा करते थे, एक–दूसरे से सलाह माँगते थे, और अपने दैनिक जीवन की योजना बनाते थे।

देश के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग परंपराएं हैं, और इनमें से प्रत्येक राज्य का समृद्ध इतिहास है जहां कई मंदिर हैं जो सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। रिलीजन के बजाय धर्म ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके विश्वदृष्टि को आकार दिया है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने की अनुमति दी है. भारत में कई अमीर मंदिर भी हैं, जो हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

मंदिर भारत में ऐसे स्थान हैं जहां लोग शांति, समृद्धि और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। इनमें से कई मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं, और उनमें से कई प्राचीन काल के दौरान बनाए गए थे और उनमें बताने के लिए आकर्षक कहानियाँ हैं। इनमें से कुछ मंदिर इतने धनवान हैं कि उनके पास विशाल भूमि या सोना है। कई मंदिरों में मूल्यवान वस्तुओं और प्राचीन वस्तुओं का व्यापक संग्रह है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है।

मंदिर एक मजबूत अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में कैसे योगदान करते हैं?

'कुछ मायनों में, तीर्थयात्रियों के साथ–साथ पर्यटन–समृद्ध आर्थिक क्षेत्रों का विकास व्यापक शोध से उपजा है, जिसने दिखाया है कि पूरे भारतीय इतिहास में मंदिर महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र थे'। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के बर्टन स्टीन ने 1960 में इस पर एक मौलिक पत्र लिखा था जिसे 'द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ ए मेडियेव्हल साऊथ इंडियन टेम्पल' कहा जाता है, जो द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज में प्रकाशित हुआ था।

एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार धार्मिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले 55 प्रतिशत हिंदू मध्य और छोटे आकार के होटलों में ठहरते हैं। धार्मिक यात्रा की लागत 2,717 रुपये प्रति दिन/व्यक्ति,

सामाजिक यात्रा की लागत 1,068 रुपये प्रति दिन/व्यक्ति, और शैक्षिक यात्रा की लागत 2,286 रुपये प्रति दिन/व्यक्ति है। यह 1316 करोड़ रुपये के दैनिक व्यय और धार्मिक यात्रा पर 4.74 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के बराबर है।

एनएसएसओ के सर्वेक्षण के मुताबिक, मंदिर की अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ रुपये या करीब 40 अरब डॉलर की है और जीडीपी का 2.32 फीसदी है। हकीकत में, यह बहुत बडा हो सकता है। फूल, तेल, दीपक, इत्र, चूड़ियाँ, सिंदूर, मूर्ती, तस्वीर और पूजा के कपड़े सभी शामिल हैं। यह असुरक्षित अनौपचारिक श्रमिकों की मेहनत और दृष्टि से प्रेरित है। यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले यात्रा और पर्यटन उद्योग भारत में 80 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिसमें साल–दर–साल 19 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर और अकेले पिछले वर्ष में $234 बिलियन से अधिक का राजस्व जमा हुआ है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, भारत में लगभग 87 प्रतिशत पर्यटक घरेलू हैं, शेष 13 प्रतिशत विदेशी पर्यटक हैं। हिंदू और बौद्ध मान्यताओं में वाराणसी के महत्व का अर्थ है कि इस प्राचीन शहर में कुल घरेलू पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का एक बड़ा हिस्सा आता है। 2022–23 के लिए केंद्र सरकार का राजस्व 19,34,706 करोड़ रुपये है, और केवल छह मंदिरों ने 24000 करोड़ रुपये नकद एकत्र किए। घरेलू धार्मिक पर्यटन विदेशी आगंतुकों की संख्या से अधिक है। नए गंतव्यों की 100 करोड़ से अधिक घरेलू यात्राओं से संकेत मिलता है कि दिल्ली–आगरा–जयपुर के सुनहरे त्रिकोण से परे मंथन चल रहा है। यहां तक कि नौ करोड़ विदेशी पर्यटकों में से 20 प्रतिशत तमिलनाडु में मदुरै और महाबलीपुरम और आंध्र प्रदेश में तिरुपति आते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट (डब्लू ई एफ) और यू एन डब्लू टी ओ पर्यटन सूचकांक जैसे प्रमुख वैश्विक सूचकांकों पर भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हुआ है। पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से होटल और रिसॉर्ट जैसे बहुउपयोगी बुनियादी ढाँचे को विकसित करने में भी मदद मिलती है। परिणामस्वरूप, भारत सरकार अगले कुछ वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के एफडीआई को आकर्षित करने का इरादा रखती है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 मिलियन नौकरियों का सृजन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर और पर्यटन उद्योग को कैसे देखते हैं?

हाल ही में, प्रधानमंत्री पर्यटन पर बजट के बाद के वेबिनार में बोल रहे थे, जब उन्होंने रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, गांधी सर्किट और सभी संतों के तीर्थों का उल्लेख किया, इस पर सामूहिक रूप से काम करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधान मंत्री ने सदियों से जनता द्वारा की गई विभिन्न यात्राओं का हवाला देते हुए कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि पर्यटन उच्च आय वाले समूहों के लिए एक फँसी शब्द है, लेकिन यह सदियों से भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है, और लोग इसका पूरी आत्मीयता से वहन करते आ रहे हैं, साधन न होने पर भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने चार धाम यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा और 51 शक्तिपीठ यात्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उनका उपयोग राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के साथ–साथ हमारे आस्था के स्थानों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह देखते हुए कि देश के कई प्रमुख शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था इन यात्राओं पर निर्भर थी, प्रधान मंत्री ने यात्राओं की सदियों पुरानी परंपरा के बावजूद सुविधाओं को उन्नत करने के लिए विकास की कमी पर खेद व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि देश की क्षति का मूल कारण सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आजादी के बाद के दशकों में इन स्थानों की राजनीतिक उपेक्षा है। मोदी ने कहा, आज का भारत इस स्थिति को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं में वृद्धि से पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि होती है। उन्होंने श्रोताओं को यह भी बताया कि जीर्णोद्धार से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में एक साल में लगभग 80 लाख लोग आते थे, लेकिन पिछले साल पर्यटकों की संख्या 7 करोड़ से अधिक हो गई। केदारघाटी में पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने से पहले केवल 4–5 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए थे। इसी तरह, 80,000 तीर्थयात्री गुजरात में माँ कालिका के दर्शन के लिए पावागढ़ आते हैं, जीर्णोद्धार से पहले सिर्फ 4,000 से 5,000 तक आते थे। सुविधाओं के विस्तार का सीधा प्रभाव है। पर्यटकों की संख्या पर प्रभाव, और अधिक पर्यटकों का अर्थ है रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रधान मंत्री ने कहा। भारत में विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डालते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि इस साल जनवरी में 8 लाख विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, जबकि पिछले साल जनवरी में केवल 2 लाख थे।

हिंदू मंदिरों का बहुआयामी महत्व है जिसमें बुद्ध, जैन और सिख मंदिर शामिल हैं।

कम्युनिस्ट और धर्मांतरण माफियाओं द्वारा हिंदू मंदिरों और धार्मिक प्रथाओं को लगातार विरोध और मजाक उड़ाया जाता है। मंदिरों ने हमेशा लोगों को एक साथ लाया है जब समाज और देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ जो नियमित आधार पर और आपात स्थिति के दौरान होती हैं, सराहनीय हैं। हाल ही में कोरोना की बड़ी आपदा और मंदिरों द्वारा दी गई सहायता ने एक बड़ी राहत प्रदान की जिसने कई लोगों की जान बचाई। स्कूलों, अस्पतालों और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए बड़े मंदिरों का कार्य काफी सराहनीय है।

वर्तमान सरकार की मंदिर स्थलों के साथ–साथ संबंधित बुनियादी ढांचे की व्यवस्थित योजना और विकास, गुलामी की मानसिकता को सांस्कृतिक रूप से बंधे हुए, सामाजिक आर्थिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित करना, अधिक सामाजिक सामंजस्य, शांति पाने के लिए जीवन का जश्न मनाने और समाज और देश के खिलाफ रची गयी साजिशों के खिलाफ एक इकाई के रूप में लड़ना।

मंदिरों का वैज्ञानिक महत्व : पृथ्वी के भीतर चुंबकीय और विद्युत तरंगें लगातार घूम रही हैं। जब आर्किटेक्ट और इंजीनियर

ISSN No. 2581-3528

एक मंदिर का डिजाइन बनाते हैं, तो वे भूमि का एक टुकड़ा चुनते हैं जहां ये लहरें प्रचुर मात्रा में होती हैं। मुख्य मूर्ति मंदिर के केंद्र में स्थित है, जिसे गर्भगृह या मूलस्थान के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण किया जाता है, और मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जानी जाने वाली पूजा के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। मूर्ति को ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है जहां चुंबकीय तरंगें बेहद सक्रिय होती हैं। जब मूर्ति रखी जा रही होती है तो वे उसके नीचे कुछ ताम्रपत्र गाड़ देते हैं। प्लेटों पर वैदिक लिपियों को अंकित किया जाता है। ये तांबे की प्लेटें पृथ्वी से चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करती हैं और उन्हें आसपास के इलाकों में विकीर्ण करती हैं। नतीजतन, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है और मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, तो उसका शरीर इन चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होता है। लगभग सभी हिंदू मंदिरों में बड़ी घंटियां होती हैं जिन्हें प्रवेश करने से पहले बजाना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान हैरान कर देने वाला है। मंदिर की घंटियाँ विभिन्न धातुओं के एक विशिष्ट अनुपात से बनाई जाती हैं। इनमें कैडमियम, लेड, कॉपर, जिंक, निकेल, क्रोमियम और मैंगनीज शामिल हैं। विज्ञान की असली वजह है मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली धातुओं का मिश्रण और अनुपात। जब घंटियां बजती हैं तो वे एक अलग आवाज निकालते हैं। ध्वनि और कंपन इतने स्पष्ट हैं कि यह मस्तिष्क के दोनों पक्षों (बाएं और दाएं) को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, तेज ध्वनि और कंपन प्रतिध्वनि मोड में सात सेकंड तक रहता है, जो शरीर के सात उपचार केंद्रों को छूने के लिए पर्याप्त है। ध्वनि के साथ मन सभी विचारों से खाली हो जाता है और मंदिरों के नियमित आगंतुक में बदल जाता है। यह बहुत ग्रहणशील हो जाता है, नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है और मन को चल रही सभी अराजकता से मुक्त कर देता है। कई अन्य लाभों में नकारात्मक विचारों का उन्मूलन, बेहतर एकाग्रता, मानसिक संतुलन और बीमारी में सहायता शामिल हैं।

मंदिर की अर्थव्यवस्था के अध्ययन को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

मंदिर और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यवस्थित प्रबंधन के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में मंदिर, उसके प्रबंधन और उसकी अर्थव्यवस्था को शामिल करना एक बुद्धिमान दृष्टिकोण होगा। युवा अपने प्रयासों और संसाधनों को मंदिर की अर्थव्यवस्था और संबंधित पर्यटन क्षेत्रों के विस्तार और विकास की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं।

एक अन्य विवादास्पद मुद्दा सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को हटाना है। सरकार को एक नया कानून पारित करना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक नेता नई मंदिर प्रबंधन समिति का भाग ना हो। दान का उपयोग उस विशेष रिलीजन या धर्म के कल्याण और सामाजिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। आइए हम मंदिर की संस्कृति और गतिविधियों को एक समकोण से देखें और मंदिर की अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।

(लेखक ब्लॉगर एवं शिक्षाविद हैं)

ISSN No. 2581-3528

समर बड़ा भीषण होगा

नरेन्द्र भदौरिया

पोरबन्दर के छोटे से राजघराने के प्रधानमंत्री करमचन्द के बेटे थे मोहनदास। करमचन्द धनी घराने के थे। उनके खानदान के लोग पंसारी बनिया थे। जो अपनी जाति पंसारी न लिखकर परम्परा से आज भी गाँधी लिखते हैं। गुजराती समाज में पंसारी विपन्न नहीं रहे। समझ और संस्कार के साथ प्रखर बुद्धि वाले रहे। उद्यम इनके रक्त की पहिचान रही है। वही स्थिति तेली (मोदी) की है। दोनों जातीय समुदाय अन्य गुजराती समुदायों की तरह सजग और स्वाभिमानी हैं। उद्यम और राष्ट्र भक्ति इनका आभूषण है। गुजरात की अगड़ी, पिछड़ी, अनुसूचित जातियों के बीच अब भेद और दूरियां नहीं बचीं। पर चुनाव आते ही इनका गणित हर राजनीतिक कार्यकर्ता बताने लगता हैं। महात्मा गाँधी के जीवन काल में उनसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि आप अगड़ी जाति के हैं या फिर पिछड़ी। पर नरेन्द्र मोदी के जातीय अपमान की राजनीतिक आँधी में बापू की जाति को भी खँगाल लिया गया।

विलुप्त हो गया हरिजन शब्द अगड़ी पिछड़ी की परिधि से ऊपर उठकर बापू ने तो हरिजन शब्द के साथ अनुसूचित जातीय समुदायों को अपनत्व का अनुभव कराया। तब गुजरात क्या पूरे देश में जातीय भेद बड़ी बुराई थी। बापू ने हरिजन समुदाय को गले लगाया। उनके हितों अधिकारों की बात करके अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ की।

गाँधी जी के रहते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बापू से यह दाँव छीनने का प्रयास किया था। बाबा अम्बेडकर कहते थे कि बापू आधे मन से अनुसूचित जातियों के सम्मान और अधिकार की बात करते हैं। पर दोनों बड़े राजनेता थे कभी कटुता के सहारे राजनीतिक सीढियां नहीं चढ़े। अम्बेडकर के मन में दीर्घ काल से उपेक्षित समाज की पीड़ा थी। उसे सहेज कर हटाने के लिए गाँधीजी की इच्छा से ही बाबा साहब को संविधान निर्माता कार्यदल का मुखिया बनाया गया था। भारतीय संविधान को ऐसा रचा गया कि इसके प्रावधानों से सम्पूर्ण देश सहमत होकर साथ खड़ा होने लगा। देश ने बापू और बाबा को दोनों नायकों को सम्मान देकर आभार जताया।

अम्बेडकर ने गाँधी के सुझाये हरिजन शब्द को संविधान से दूर रखा। उन्होंने अनुसूचित जाति शब्द दिया। बहुत बाद में भारत की राजनीति में काशीराम का अवतरण हुआ। हिन्दू समाज की इस दरार को उन्होंने गहरा करने की ठानी। काशीराम ने तो गाँधी के हरिजन और बाबा साहब के अनुसूचित दोनों शब्दों से इतर दलित शब्द उछालकर हरिजन शब्द को शब्दकोश तक सीमित कर दिया। बापू के नाम को रटने वाली कांग्रेस के किसी नेता के मुँह से अब कभी हरिजन शब्द सूने में भी सुनायी नहीं पड़ता।

उपकार जो उपहार बना : गाँधीजी ने अपना जातीय विशेषण जवाहर लाल नेहरू को व्यथा में देखकर इन्दिरा के साथ उनके मुस्लिम पति फिरोज को अलंकरण की तरह दे दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि जवाहर लाल संसार के समक्ष दिखावा कर रहे होंगे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध दुलारी बेटी इन्दिरा ने हिन्दू धर्म त्याग दिया। उन्हें भय सता रहा होगा कि भारत के हिन्दू मतों पर वह अपना दावा कैसे बनाये रख सकेंगे। ऐसी दुविधा में तब बापू का गाँधी शब्द अलंकरण जवाहर लाल के बड़े काम आया था। गाँधी शब्द की ओट में छद्म हिन्दू बनने का ढोंग चल पड़ा। हिन्दू होने पर गर्व नहीं। जवाहर लाल को वैसे तो हिन्दू घर की सन्तान होने पर कभी गर्व नहीं हुआ। वह स्वभाव से अंग्रेजी मानसिकता के थे। जबकि अपने राजनीतिक चरित्र को ऐसे गढ़ते रहे जिससे चीन और रूस के वामपन्थी यह समझें कि भारत जवाहर के पीछे चलते हुए एक दिन उनकी राह पर आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे बहुकोणीय राजनेता की लाडली इन्दिरा क्या सचमुच अचानक हिन्दू लीक छोड़कर मुस्लिम बन गयी होगी। फिरोज खान उनके परिवार विशेषतः जवाहर लाल की बीमार पत्नी की देखभाल के नाम पर बेटी इन्दिरा की निकटता को लपकने में सफल हो गया। फिर प्यार की अँधेरी गली की गहराई बढ़ती चली गयी। बाबू के पास जवाहर लाल जब रुआँसा मुँह लेकर गये होंगे तो उस पल की कल्पना कीजिए। बापू के सामने खड़े उस प्रगतिवादी नेता ने क्या हिन्दुत्व से लगाव की बात की होगी। उनसे कहा होगा– बापू भारतीय समाज मुझे ठुकरा तो नहीं देगा। बापू दूर तक निहारने में सिद्ध थे। गाँधी नाम का उपहार देकर कहा होगा जाओ इसके बल पर बेटी दामाद दोनों को सहेज लो। इससे जवाहर लाल तो खुश हुए ही बेटी इन्दिरा और दामाद फिरोज दोनों प्रफुल्ल हो उठे। दोनों राजनीति में जम गये।

जवाहर की जाति नेहरू विलीन हो गयी। गाँधी के अपने बेटों की राह बदलती रही। पर इन्दिरा की सन्ततियों ने गाँधी नाम का उपहार कभी नहीं छोड़ा। इन्दिरा के बड़े बेटे ने इटली की सोनिया से प्रेम किया जबकि छोटे संजय ने भारत के पंजाबी परिवार की बेटी संग ब्याह रचाया। इन्दिरा का कुनबा जैसा भी है उसने बापू

की भेंट को सिर पर बाँधे रखा। राहुल उनकी बहन प्रियंका दोनों गाँधी नाम की माला जप रहे हैं। देश से कह रहे हैं कि हम तो हिन्दू हैं। हम तो कट्टर सत्याग्रही गाँधी की सन्तति हैं। दावे से कहते हैं – हम गाँधी हैं सावरकर या कोई और नहीं।

राहुल जो हैं उसे स्वीकारते नहीं राहुल जो कुछ सिद्ध करने में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं, वह वो हैं ही नहीं। वह गाँधी कैसे हो सकते हैं जब उनकी माँ पिता दोनों ईसाई के नाते चर्च में विवाह रचाकर जीवन साथी बने थे। बहन ने तो इसी देश के ईसाई नवयुवक वाड्रा से विवाह रचाया। इस परिवार ने कभी अपना मतान्तरण भी नहीं कराया। कांग्रेस की विवशता जानकर भी उसके नेता बौराये फिर रहे हैं। चुटीले घटिया और जहरीले शब्दबाण राहुल को थमाते हैं कि इनसे मोदी तिलमिला उठेंगे। यह भूल जाते हैं मोदी की सेना कितनी सुगठित और सशक्त है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार राहुल के चलते निरन्तर खिसकता जा रहा है। यह सत्य चिल्लाकर कौन कहे।

विदेशी कुनबे की अकुलाहट : डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी तो कहते हैं कि राहुल की भारतीय नागरिकता जा सकती है क्योंकि इनके पास दूसरे देशों की छद्म नागरिकता भी है। अपने दावे को वह न्यायालय में सिद्ध करने की बात करते हैं। जो भी हो न्यायालय के एक आदेश से राहुल पर जो संकट आया है उससे भारत में उतनी उलझन किसी को नहीं है जितनी अमेरिका और जर्मनी की सरकारों को है। दोनो देशों की सरकारों के प्रवक्ता कहते हैं कि वह आँखें गड़ा कर निहार रहे हैं कि राहुल के साथ क्या हो रहा है। वैसे भारत की मोदी सरकार ही नहीं देश की जनता भी अब अमेरिका या जर्मनी के घूर कर देखने से तनिक भी विचलित नहीं है। वह दिन लद गये जब किसी के घूरने से भारत काँप उठता था। भारत अपनी सम्प्रभुता से छेड़छाड़ करने का दुस्साहस किसी को नहीं करने देगा। घमण्ड त्याग कर उन्हें मुँह और आँखे बन्द करके चुप बैठना चाहिए।

देश के भीतर और बाहर जो हो रहा है उसकी समीक्षा का अवसर हर भारतीय नागरिक को मिल गया है कि सागर की अतल गहराईयों के उस पार राहुल के इन शुभचिन्तकों की वास्तविक पीड़ा क्या है। सोनिया राहुल प्रियंका का यह परिवार वेटिकन का चहेता है। वेटिकन ईसाई सत्ता का केन्द्र है। भारत में बढ़ता ईसाई मतान्तरण इस परिवार की राजनीतिक शक्तियों से पोषित होता आया है। राहुल कहते हैं वह राजनीति के गलियारे से नहीं कुछ समय के लिए संसद से बाहर हुए हैं। पर उनके साथ ऐसा होना पूरे ईसाई विस्तार तंत्र के लिए बड़ा अशुभ संकेत है। ईसाई मठाधीशों के दबाव में क्या राहुल के प्रति न्यायालय का रुख पलट जाएगा। विदेशी कूट रचनाकार तो इतना ही चाहते हैं।

हास्यास्पद स्थिति : अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सत्ता से दूर रखने के लिए न्यायालय की देहरी तक घसीट कर ले जाने की तैयारी हो रही है। इतने पर भी अमेरिका भारत की ओर घूरने की बात कहता है। जबकि राष्ट्रपति बाइडन को यूक्रेन पर रूसी आक्रमणों को रोकने के लिए भारत का साथ चाहिए। अमेरिका मानता है कि भारत उसका मित्र देश नहीं है। पर एक लालच दिखाता है कि चीन से रार की स्थिति में वह भारत के साथ स्वतः आ सकता है। बार–बार ऐसी रिपोर्ट जारी करता है कि भारतीय सीमा पर चीन और पाकिस्तान सेना बढ़ा रहे हैं। जर्मनी को छलनी में दूध दुहते अब तक कुछ नहीं मिला। वह भारत के साथ आर्थिक अनुबन्ध बढ़ाना चाहता है। राहुल के बचाव के नाम पर घूरा घूरी तो बहाना है।

एक और बात साफ है कि ईसाई राज्य वेटिकन के साम्राज्य के दबाव में 1980 से 90 की अवधि में अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों ने अपने अपने यहाँ एक विधान बनाया था। उसके अनुसार संसार के जिस किसी देश में ईसाई मिशनरी संगठनों को वहाँ की सरकार काम करने में अड़चनें डालेगी तो उस पर ईसाई प्रभुत्व वाले सशक्त देशों की सरकारें मिलकर दबाव बनाएंगी। आर्थिक प्रतिबन्ध का भय दिखाएंगी। कूटनीतिक प्रयत्न करके मिशनरियों को अनुकूलता प्रदान करेंगीं।

मोदी की वापसी का डर : भारत में 2024 में आम चुनाव होंगे। नरेन्द्र मोदी फिर सत्ता में वापसी करते संसार के कूटनीतिज्ञों को दिख रहे हैं। यह वापसी कहीं इतनी सशक्त हो गयी कि फिर ईसाई–मुस्लिम–वामपन्थी गठजोड़ से भी बात न बन पायी तो अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी सही हो जाएगी कि भारत संसार की बड़ी महाशक्ति बनकर उभरेगा। इसी आशंका को रोकने के लिए सारी भारत विरोधी शक्तियां अपने दबे कुचले घोड़ों को उकसाकर खड़ा कर रही हैं। हर किसी की आँखों की किरकिरी नरेन्द्र मोदी है। आने वाले चुनाव में छोटा से छोटा बिलौटा भी सिंह बनकर दहाड़ने का दम भर रहा है। परकीय शत्रु अशक्त बिडालों पर भी धन वर्षा कर सकते हैं जो किसी तरह सत्ता से मोदी को दूर रखने में सहायक बनते प्रतीत हों। सभी का मानना है कि इस बार का संग्राम बहुत रोचक होगा।

राजनीतिक अंधता का दोष : राजनीतिक अंधता एक बड़ा रोग है जिसके कारण भारत एक हजार साल तक दासता का कोढ़ सहता रहा। यह अंधता और कुछ नहीं गुटों खेमों में बँटकर भारत की विरोधी शक्तियों को बलवान बनाने की नासमझी रही है। भारतीय जनमानस को भ्रमित करने के नाना कुचक्र सभी ओर से होंगे। देखना होगा कि भारत की आत्मा के शत्रु कहीं इतने बलिष्ठ न हो जाएं कि भारत फिर से अशक्त होकर हाँफता खड़ा रह जाय। इसीलिए राष्ट्रवादी पूरी शक्ति से समर में उतरने की तैयारी में लग गये हैं।

(लेखक राष्ट्रवादी विचारक एवं लेखक हैं)

मेरा गांव मेरा परिवार

प्राचीन समय में भारत में ग्रामीण जीवन शैली थी। जिसमें अपनापन था, जिसमें एक दूसरे के लिये कुछ करने की इच्छा रहती थी। धीरे-धीरे जब गांव का शहरीकरण होना शुरू हुआ तो ये अपनेपन का भाव कम होने लगा। इस अपनेपन के भाव को राजस्थान के नेठराना गांव ने फिर जीवित कर दिया। जंहा सगे संबन्धी अपनों से दूर चले जाते हैं वंही नेठराना गांव ने अपने गांव की बेटी को भात भरकर मेरा गांव मेरा परिवार के भाव को जीवित कर दिया। राजस्थान के नेठराना गांव की बेटी मीरा की शादी हरियाणा में हुई थी। मीरा के पिता व भाई की मृत्यु हो चुकी है नेठराना गांव में मीरा का कोई सगा सम्बन्धी नहीं है। मीरा के पति की भी मृत्य हो चुकी है। मीरा का न पति है न पिता है और न ही भाई है। बस उसकी दो बेटियां हैं। अपनी बेटी की शादी में परम्परा को निभाते हुए मीरा अपने गाँव नेठराना में भात नोतने गई तो भाई तो नहीं पर भाई की एक छोटी सी झोपड़ी गांव में ही है। भाई की उस झोपड़ी को भाई मानकर मीरा ने झोपड़ी का तिलक करके बेटी की शादी में भात भरने का निमंत्रण दिया।

उस समय मीरा बहुत भावुक थी, आंख में आंसू भरे थे। पर इस पीड़ा को गांव में किसको सुनाए कोई अपना भी नही है। मीरा के उन आंसुओ की पीड़ा को नेठराना गांव में लोगों ने समझा और पूरे गांव ने अपने गांव की बेटी मीरा की बेटी की शादी में भात भरने का फैसला लिया। पूरा गांव बेटी मीरा के घर शादी में भात भरने गए जो चर्चा का विषय बन गया। जितना भात गांव के लोगों ने भरा उतना शायद मीरा के सगे भाई भी न भरते। गांव वालों ने सात लाख रुपये नकद जेवर व कपड़ों सहित लगभग दस लाख का भात भरा। नेठराना गांववासियों ने मीरा को बता दिया कि मीरा पूरे गांव की बेटी है।

नेठराना की इस साहसिक व सराहनीय पहल से पूरे देश को सीख लेनी है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अपनों के लिए समय नहीं दे पाते, सगे सम्बन्धों को भी समाप्त करने की ओर व्यक्ति बढ़ गया है। ऐसे में नेठराना गांव की प्रेरणा अपनों को अपने से मिलाने की लिए ही है। इसी परम्परा की वजह से गांव में कोई गरीब नही था। कोई भूखा नही रहता था। हर त्यौहार को सभी सुखपूर्वक मनाते थे। परन्तु सम्बन्धों को भुलाकर पैसा कमाने की होड़ ने व्यक्ति को सबसे दूर कर दिया है। बड़े-बड़े शहरों में बनी बड़ी-बड़ी कालोनियों में पड़ोसी-पड़ोसी को नही जानता जिसके कारण उनके सुख-दुख में सहभागी भी नही हो पाता। नेठराना गांव की तरह अगर भारत का प्रत्येक गांव व शहर सोच ले तो भारत का कोई भी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस नही करेगा।

(ललित शंकर गाजियाबाद)

ISSN No. 2581-3528

अर्थव्यवस्था के निज मॉडलों से ही भारत बनेगा आर्थिक महाशक्ति : एक समीक्षा

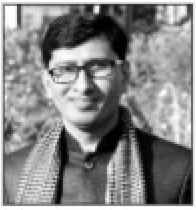

डॉ. आशीष कुमार

अर्थव्यवस्था के प्रचलित प्रतिमान दुनिया की मौजूदा जटिल आर्थिक चुनौतियों को सुलझाने में असक्षम हैं। अमेरिका में डूबते बैंक, चीन में पैदा होती आर्थिक असमानता, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए युद्धों को सहारा लेते अमेरिका जैसे देश, इस बात का प्रमाण है। इन हालातों में अर्थव्यवस्थाओं के उन प्रतिमानों की आवश्यकता है, जो दुनिया की वास्तविक समस्याओं का निदान कर सकें, जटिलताओं और सामाजिक असमानताओं को दूर कर सकें, विकास के उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, जिससे पर्यावरण की चिंताओं को महत्व दिया गया हो। जिन प्रतिमानों में आर्थिक विकास की सफलता मानव विकास से आंकी जाती है।

तेजी से आर्थिक विकास कर रहे भारत को तीन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और पर्याप्त आय के साथ सुरक्षित रोजगार के अवसर मुहैया कराना। इन समस्याओं का सामना दुनिया के लगभग सभी देशों को करना पड़ रहा है। ऐसे दुनिया के देशों को अर्थव्यवस्था के नए प्रतिमानों की आवश्यकता है ताकि इन मुद्दों को कुशल तरीके से सुलझाया जा सके।

वर्तमान में प्रचलित अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल अत्यंत रैखिक, अत्यधिक गणितीय और यांत्रिक हैं, इन विशेषताओं को इनकी बुनियादी खामी के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान अर्थशास्त्री, टिनबर्गेन थ्योरी को उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र आर्थिक संस्थान होने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए मुक्त व्यापार नीतियों को आवश्यक बताया गया है। इन नीतियों में पश्चिम के

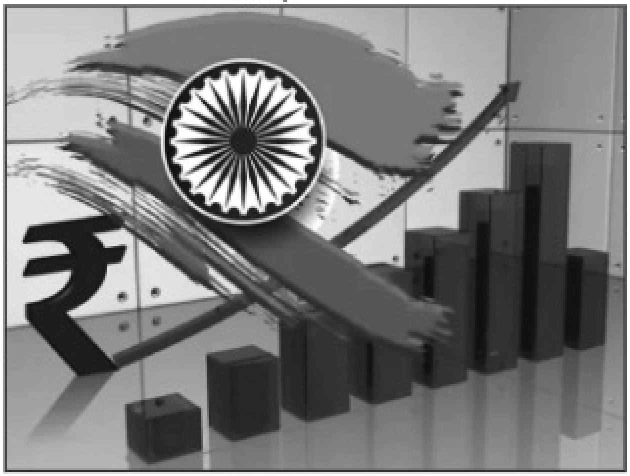

विकसित देशों का अधिक फायदा दिखता है ताकि वे विश्व बाजार में अपने माल की खपत बेरोकटोक कर सकें। मौजूदा प्रतिमानों में आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया जाता है, इसमें मानवीय पहलुओं को विकास के मानदंडों लिए उचित जगह नहीं दी जाती है, यही कारण है कि इन प्रतिमानों की आलोचना की जाती है।

कोविड–19 महामारी ने इन प्रतिमानों की अपर्याप्तता और अक्षमता को उजागर कर दिया है। समय–समय पर दुनिया में आने वाली आर्थिक मंदी के लिए भी प्रचलित प्रतिमानों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ प्रमुख चुनौतियां जैसे आय असमानता, संसाधन क्षरण, जलवायु परिर्वतन, ग्लोबलाइजेशन के कारण रोजगार विस्थापन की समस्या, डिजिटल एकाधिकार का उदय आदि गंभीर समस्याएं हैं।

इन हालातों में विश्व को एक नए अर्थशास्त्र की आवश्यकता है जो सामाजिक, आर्थिक प्रणालियों की जटिलताओं को ध्यान में रखे और मानव विकास को आर्थिक विकास के रूप में देखे। भारत के नीति निर्माताओं को एक ऐसा समाधान पाना होगा, जहाँ एक ही समय में आर्थिक वृक्ष के फल भी पाए जा सकें और उसकी जड़ों को मजबूत भी किया जा सके। इसके लिये वर्तमान रैखिक एवं यांत्रिक प्रतिमान को छोड़ने और अर्थशास्त्र के प्रति अधिक समग्र एवं अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

नए प्रतिमानों से सकारात्मक संभावनाएं

♦ **आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण** : यह आर्थिक विकास के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण पर बल देता है जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखता है।

♦ **विकास के कारक :** आर्थिक विकास गति देने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण के महत्त्व पर गौर करना।

♦ **समावेशी विकास :** इसमें अधिक समावेशी विकास की आवश्यकता पर गौर किया जाएगा, जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों के बजाय समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करता हो। इसके अतिरिक्त, यह जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार्यता को प्रोत्साहित करेगा।

लक्ष्य हासिल करने के तरीके

♦ **एक समग्र और व्यापक पहल करना :** सरकार, शिक्षा जगत, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और स्थानीय समाज को शामिल करते हुए समन्वय के साथ लक्ष्यों को हासिल करना। यह मौजूदा मुद्दों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान रखते हुए एकीकृत समाधान विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श और संसाधनों का प्रयोग करना है।

– किसी योजना के निर्णय और नीति निर्माण के लिए सूचना तंत्र को विकसित और मजबूत करना। निगरानी, मूल्यांकन और प्रगति पर नज़र रखने, अंतरालों की पहचान करने और साक्ष्य एवं प्राप्त अनुभवों के आधार पर फैसले लेना।

मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू

♦ **शिक्षा में निवेश:** शिक्षा में निवेश के जरिए सरकारें और संगठन लोगों के कौशल एवं ज्ञान को विकसित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न हो सके।

♦ **स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना :** स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और स्वस्थाय के प्रति लोगों में जागरूगता पैदा करना। अच्छा स्वास्थ्य उत्पादक जीवन जीने में मदद कर सकता है।

स्थानीय समस्याओं के लिए अनुकूल समाधान:

समस्या और जरूरतों का आंकलन करना: स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझना महत्त्वपूर्ण है। सर्वेक्षणों, फोकस समूहों और समुदाय के सदस्यों के साक्षात्कार के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।

अवसंरचना और संसाधनों को मजबूत करना: जीरो से शुरू करने के बजाय, स्थानीय रूप से मौजूदा अवसंरचना और संसाधनों के आधार पर समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का उपयोग कर सकता है।

समाधान को आवश्यक लोगों तक पहुंचना : यह सुनिश्चित करने के लिये कि समाधान प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें, समुदाय के सदस्यों संवाद और फीडबैक को मजबूत करना।

–समावेशी, समाधानों के लिए मानव–केंद्रित सिद्धांतों का उपयोग करना।

–स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना ताकि वे समाधानों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

सहकार्यता और समन्वय को बढ़ावा देना:

–सहकार्यता एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी संचार और संवाद महत्त्वपूर्ण है।

–लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करना, जिनके लिये सभी हितधारक मिलकर कार्य कर सकते हैं।

विश्वास का निर्माण करना: सहकार्यता और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए आपसी विश्वास निर्माण करना, विश्वास निर्माण और सहकार्यता को बढ़ावा देने के लिए संचार और संवाद आवश्यक अंग है।

नवाचार को अपनाना: नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना होगा।

नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना: नई प्रौद्योगिकियों के साथ अद्यतन बने रहने की आवश्यकता है, जो समस्याओं को अभिनव तरीकों से हल करने में मदद कर सकती हैं और जोखिम लेने के रवैये को प्रोत्साहित करती हैं।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना:

♦ **वंचित समाज को अवसर देना:** समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये, हमें महिलाओं, जातीय अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजन जैसे वंचित, उपेक्षित समूहों के लिये अवसर सृजित करने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, रोज़गार और अन्य संसाधनों तक पहुँच शामिल है।

भेदभाव उन्मूलन: समावेशिता और सामाजिक न्याय के लिये भेदभाव एक प्रमुख बाधा है। समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये हमें नस्लवाद, लिंगवाद और अन्य भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

नए प्रतिमानों को लागू करने में चुनौतियां : कुछ संभावित चुनौतियाँ जो उभर सकती हैं –

– पहले से अनुचित आर्थिक लाभ ले रहे समूहों की ओर से प्रतिरोध

– यदि ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो असमानता में वृद्धि की संभावना।

– पुरानी धारणाओं के बदलने में होने वाले संघर्ष को समझना

– पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और उन भू–राजनीतिक दिक्कतों का सामना करना।

– इसके अतिरिक्त, नए आर्थिक प्रतिमान को लागू करने के लिए नीति और विनियम के स्तर पर चुनौतियां।

(लेखक मीडियाविद हैं)

विकास की वेदी पर आदिवासी समाज

शुभम यादव

1991 में नई औद्योगिक नीति पर अमल करने के बाद भारत में एक नये तरह की विकासवादी लहर का प्रवेश हुआ। भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देने लगा। तेजी के साथ विकास के नाम पर निजीकरण की प्रक्रिया को खूब बढ़ावा मिला और कम्पनियों का तेजी के साथ भारत में प्रवेश शुरू हुआ। कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल की तलाश थी और यह कच्चा माल उन्हें आदिवासी इलाके में ही मिल सकता था। इसलिये उन्होंने आदिवासी इलाकों में अपनी जड़ें जमायी और संसाधनों की लूट का सिलसिला बड़ी बेशर्मी से चालू हुआ। हिमांशु कुमार के संस्मरण 'विकास आदिवासी और हिंसा' में आदिवासी समाज पर भूमण्डलीकरण के प्रभावों को रेखाँकित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जीवन की दास्तानों का एक नया अध्याय खुलता है, जिसमें आदिवासी समाज में विकास की तत्कालीन स्थिति को आसानी से देखा और समझा जा सकता है।

निजीकरण की प्रक्रिया को विकास की झलक के रूप में देखा जा रहा है। कम्पनियों को रोजगार की जननी के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है, लेकिन स्थिति इससे उलट है। जिस आदिवासी इलाके में ये कंपनियाँ लगी हैं वहाँ आजादी के सात दशक बाद भी 'हमने देखा कि गाँव में स्कूल चल रहा है चालीस साल से लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। राशन की दुकान तो है पर साल में दो बार राशन आता है।' यह आँकड़ा कितना भयावह है कि वहाँ कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। वहां आधुनिक किस्म की शिक्षा तो दूर पारंपरिक किस्म की शिक्षा का भी अभाव है। राशन की भारी समस्या है। स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। जिन कम्पनियों को विकास की जननी घोषित किया जा रहा है, रोजगार के बहुत बड़े केन्द्र के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ आदिवासियों के लिये कौन सा रोजगार और किस तरह का रोजगार है? क्या ये कम्पनियाँ जिनका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, वे उन अकुशल आदिवासियों को सम्मानजनक रोजगार दे सकती हैं ? मेरा उत्तर है नहीं!

जिन्हें कम्पनियों से विकास का स्वप्न दिखायी देता है उनकी बुद्धि का क्या कहना। वे शायद पूँजी के लाभ और हानि के सिद्धान्त को भूल जाते हैं, वे यह भी भूल जाते हैं कि कोई भी व्यापार मुनाफे पर टिका होता है। कम्पनियों का मूल चरित्र सिर्फ और सिर्फ़ मुनाफा कमाना होता है विकास करना नहीं। पूँजीपतियों ने विकास के नाम पर आदिवासी इलाकों में बड़ी–बड़ी मशीनें लगायीं। विकास और रोजगार का झाँसा देकर आदिवासियों को जमीनों से बेदखल कर दिया। आदिवासियों को उनकी जमीनों से विस्थापित किया जा रहा है। उनके पारंपरिक खेती के कार्यों को नष्ट किया जा रहा। अत्याधुनिक मशीनों के चलते उनके पारंपरिक कलाओं जिसके द्वारा वे

जीवनयापन करते थे उससे उन्हें दूर किया जा रहा है। यह उसी तरह का आदिवासी इलाकों में एक नया अर्थतंत्र है, जैसे मध्यकालीन गांवों में ब्रिटिश अर्थतंत्र। विकास के नाम पर उनकी हस्तकलाओं, खेती आदि को समाप्त किया जा रहा और शहरों का निर्माण हो रहा है। इसके चलते आदिवासी समाज के लोग मजदूरी, बधुआ मजूदरी करने व खानाबदोश का जीवन जीने को अभिशप्त हैं। विकास का यह ऐसा मॉडल है जिसमें गरीब, गरीब ही बना रहता है। आज तक की विकास परियोजनाओं की विशेषता यह है कि 'आजादी के बाद से आज तक एक भी प्रोजेक्ट बिना पुलिस और बंदूक के लगाया ही नहीं गया।' यह दमनात्मक और लूट का सिलसिला औपनिवेशिक भारत का नहीं, बल्कि आजाद भारत का है। जैसे अंग्रेजी राज के बारे में उसकी सत्ता और विकास के बारे में, यह सच था कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता उसी तरह कम्पनियों के बारे में भी यह सच है कि कम्पनियों के द्वारा हुआ कथित विकास अवाम का बिना खून बहाये नहीं हो सकता।

आदिवासी समाज के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हें अपनी जमीनों के मुआवजे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं और अपने अधिकारों के लिये आवाज उठाने पर नक्सलवादी कहकर पूँजीपतियों की सहायता करना सरकार का धर्म बन गया है। हक और हुकूक के लिए उठने वाली ऐसी आवाजों को कुचलने में सरकारें माहिर हैं। वही कम्पनियां जो विकास और रोजगार की जननी मानी जाती है वे सामाजिक भागीदारी व उसके विकास के बजाय अपना लाभ हानि दिखाई देता है। भारतीय मीडिया भी आदिवासियों के साथ हुई घटनाओं पर सदैव उदासीन ही रही। वहीं सरकारें भी नक्सलवाद को सामाजिक व आर्थिक समस्या के रूप देखने के बजाय राजनीतिक समस्या के रूप में व्याख्यायित करती रही हैं। वे इस बात पर भी विचार नहीं करना चाहती कि नक्सलवादी क्षेत्रों में 'लोग 20–40 रुपये की औसत दैनिक मजदूरी पर जीने को मजबूर हैं। इसके साथ अन्य प्रकार के दबाव व शोषण अलग से हैं।' नक्सलवाद का संबंध आर्थिक समस्याओं से बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। इस गंभीर समस्या को लगातार बढ़ रही गहरी आर्थिक विषमता को समाप्त करके व सामाजिक धरातल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऐजेंडे पर चल कर कुछ हद तक समाप्त करने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ा जा सकता है।

बहरहाल, तीसरी दुनिया के तमाम देशों में हो रहे विकास का आलम यही है। हर जगह आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। दुनिया भर में जंगलों, पहाड़ों, खनिजों को लूटा जा रहा है। वैश्वीकरण का स्वप्न जो एक संस्कृति में विश्वास करता है बहुत ही भयावह है। पूँजीवाद की संस्कृति को बनाये रखने के लिये आदिवासी सरीखे तमाम विभिन्न संस्कृतियों का खात्मा किया जा रहा है। विकास के नाम सामाजिक विषमता की खायीं बढ़ती जा रही है। हर रोज उद्योग और रोजगार के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा और हम चुप हैं। जिस सपने को लेकर हमने इस विकास के मॉडल को अपनाया था वह हमारी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है और इसके कारण आज हमारे सामने नई चुनौतियाँ उपस्थित हुई हैं। हमें इस विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

(लेखक, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में शोधार्थी हैं)

केशव संवाद मासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें एवं केशव संवाद को सोशल मीडिया पर FOLLOW करें।

FACEBOOK

Keshav Samvad @keshavsamvad @KeshavSamvad samvadkeshav

ISSN No. 2581-3528

मीडिया सुर्खियां (01 मार्च 2023 – 31 मार्च 2023)

01 मार्च : लखनऊ : शाहरुख खान की पत्नी गौरी पर गैर जमानती धारा 409 के तहत FIR दर्ज।

02 मार्च : प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI कमेटी बनाकर करें CEC और EC की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट।

03 मार्च : प्रयागराज : अतीक अहमद के गुर्गों के घर पर आज फिर चलेगा PDA का बुलडोजर।

04 मार्च : उज्जैनः विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सुबह–सुबह महाकाल मंदिर पहुंचे, भस्म आरती में हुए शामिल।

05 मार्च : विमेंस प्रीमियर लीग में खेल रही एकलौती अमेरिकी खिलाड़ी तारा नॉरिस ने पहले ही मुकाबले में अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया। नॉरिस ने आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 29 रन दिए और 5 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही वो डब्लूपीएल के इतिहास में एक मैच में पांच विकेट झटकने वाली पहली गेंदबाज बन गईं।

06 मार्च : भारतीय तट रक्षकों ने गुजरात के अरब सागर से 425 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ को किया बरामद।

07 मार्च : पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीएसएफ ने कल्याणी सीमा चौकी क्षेत्र के एक तालाब से करीब 2.57 करोड़ रुपये के सोने के बिस्किट बरामद किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

♦ पूरे भारत में होली का जश्न, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी रंगों के त्योहार की शुभकामनाएं।

08 मार्च : जम्मू–कश्मीर के बारामूला में लश्कर–ए–तैयबा के सहयोगी और आतंकी संगठन TRF के दो दहशतगर्दों को सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला–बारूद बरामद हुआ है।

09 मार्च : अमेरिकी संसद में एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है।

10 मार्च : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को असम के तिनसुकिया जिले में साल 1994 में उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना द्वारा मारे गए पांच युवकों के परिवारों को 20–20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

11 मार्च : दिल्ली शराब घोटालाः के कविता से ED की पूछताछ जारी, तेलंगाना भवन में BRS समर्थकों का प्रदर्शन।

12 मार्च : दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, स्वाति मालीवाल का कहना है कि पिता उनका यौन शोषण करते थे। वह अलग बात है कि वर्ष 2016 में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि 'मैं फौजी की बेटी हूं। फौज में पली बढ़ी हूं। देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है। मुझे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती।'

13 मार्च : ऑस्कर्स 2023 में भारत का डंका। भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू–नाटू को बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग का खिताब मिला है। इसके साथ ही भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने भी अवॉर्ड जीत लिया है।

14 मार्च : दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया, कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है, इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, वहीं तमाम लोग इसमें घायल भी हुए थे और बड़ी संख्या में लोगों और सरकार की प्रॉपर्टी की भी क्षति हुई थी।

15 मार्च : जम्मू–कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने मंदिर में दर्शन किए, मुफ्ती पुंछ के देरियां में नवग्रह मंदिर के दर्शन करने गईं और मुफ्ती ने मंदिर में दर्शन के दौरान शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया।

16 मार्च : अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में मांडला के समीप सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में दो पायलट की मौत हो गई।

17 मार्च : PM मोदी और PM शेख हसीना ने किया भारत–बांग्लादेश की 'फ्रेंडशिप पाइपलाइन' का उद्घाटन।

– अग्निवरों के लिए MHA का बड़ा फैसला, BSF के बाद अब CISF की भर्तियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

18 मार्च : UP: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा।

19 मार्च : पैदल चाल में विकास और परमजीत सिंह को ओलंपिक टिकट, एशियाई चैंपियनशिप में जीता रजत और कांस्य।

20 मार्च : नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हासिल किया।

21 मार्च : पंजाब : खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पर NSA के तहत केस दर्ज। लुक आउट नोटिस जारी, देश के सभी एयरपोर्ट और बंदरगाह पर अलर्ट।

22 मार्च : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने वर्ष 2023 के लिए 54 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।

23 मार्च : सूरतः मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा, तुरंत जमानत भी मिल गई।

24 मार्च : जस्टिस रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।

25 मार्च : भारतीय बॉक्सर नीतू घनघस ने रचा इतिहास, मंगोलिया की पहलवान (48KG) को हराकर बनीं वर्ल्ड चैंपियन।

26 मार्च : दिल्ली और मुंबई के बीच ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम मे खेले गए WPL फाइनल मुकबले में मुंबई की टीम ने दिल्ली को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 की ट्रॉफी जीत ली है।

28 मार्च : उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, दिनेश पासी और शौलत हनीफ को उम्रकैद की सजा, केस में अतीक के भाई अशरफ समेत सात बरी।

29 मार्च : Kuno नेशनल पार्क में नामीबिया से आई मादा चीता सियाया ने दिया 4 बच्चों को जन्म, पीएम मोदी ने दी बधाई।

30 मार्च : हरिद्वार में बोले गृह मंत्री शाह– आज भारत के पास अपनी शिक्षा नीति।

31 मार्च : बिहार, गुजरात और प. बंगाल में राम नवमी की रैली पर पत्थरबाजी, कई लोग घायल।

संयोजन : प्रतीक खरे

एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी

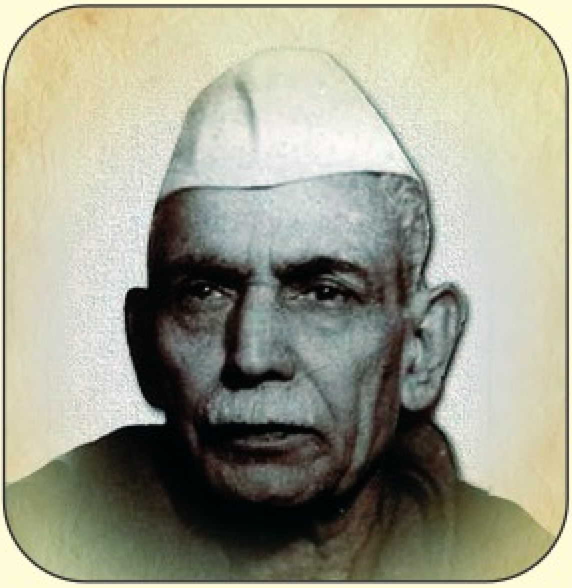

श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल, 1889 को ग्राम बाबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में श्री नन्दलाल एवं श्रीमती सुन्दराबाई के घर में हुआ था। उन पर अपनी माँ और घर के वैष्णव वातावरण का बहुत असर था। वे बहुत बुद्धिमान भी थे। एक बार सुनने पर ही कोई पाठ उन्हें याद हो जाता था। चौदह वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। इस समय तक वे 'एक भारतीय आत्मा' के नाम से कविताएँ व नाटक लिखने लगे थे।

1906 में कांग्रेस के कोलकाता में सम्पन्न हुए अधिवेशन में माखनलाल जी ने पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के दर्शन किये। अपने तरुण साथियों के साथ उनकी सुरक्षा करते हुए वे प्रयाग तक गये। तिलक जी के माध्यम से वे क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये। महाराष्ट्र के क्रान्तिवीर सखाराम गणेश देउस्कर से दीक्षा लेकर उन्होंने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये। फिर उन्होंने पिस्तौल चलाना भी सीखा।

इसके बाद उनका रुझान पत्रकारिता की ओर हो गया। उन्होंने अनेक हिन्दी और मराठी के पत्रों में सम्पादन एवं लेखन का कार्य किया। इनमें कर्मवीर, प्रभा और गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप प्रमुख हैं। वे श्रीगोपाल, भारत सन्तान, भारतीय, पशुपति, एक विद्यार्थी, एक भारतीय आत्मा आदि अनेक नामों से लिखते थे। खंडवा से उन्होंने 'कर्मवीर' साप्ताहिक निकाला, जिसकी अपनी धाक थी।

1915 में उनकी पत्नी का देहान्त हो गया। मित्रों एवं रिश्तेदारों के आग्रह पर भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। अब वे सक्रिय रूप से राजनीति में कूद पड़े और गाँधी जी के भक्त बन गये। गांधी जी द्वारा 1920, 1930 और 1940 में किये गये तीन बड़े आन्दोलनों में माखनलाल जी पूरी तरह उनके साथ रहे।

गांधी जी के अतिरिक्त उन पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस आदि सामाजिक व आध्यात्मिक महापुरुषों का बहुत प्रभाव था। उनके ग्रन्थालय में अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों की पुस्तकों की भरमार थी। खंडवा (मध्य प्रदेश) में रहकर उन्होंने अपनी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से समाजसेवा का आलोक चहुँदिश फैलाया।

माखनलाल जी को सन्तों की कविताएँ बहुत पसन्द थीं। निमाड़ के सन्त सिंगाजी से लेकर निर्गुण और सगुण सभी तरह के भक्त कवियों और सूफियों की रचनाएँ उन्हें प्रिय थीं। वे पृथ्वी को अपनी माता और आकाश को अपने घर की छत मानते थे। विन्ध्याचल की पर्वतशृंखलाएँ एवं नर्मदा का प्रवाह उनके मन में काव्य की उमंग जगा देता था। इसलिए उनके साहित्य में बार-बार पर्वत, जंगल, नदी, वर्षा जैसे प्राकृतिक दृश्य दिखायी देते हैं।

माखनलाल जी के साहित्य में देशप्रेम की भावना की सुगन्ध भी भरपूर मात्रा में दिखायी देती है। 'एक फूल की चाह' उनकी प्रसिद्ध कविता है -

मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक।
मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जायें वीर अनेक।।

गांधी जी के अनन्य भक्त होने के कारण उन पर माखनलाल जी ने बहुत सी कविताएँ एवं निबन्ध लिखे हैं। लोकमान्य तिलक एवं जवाहरलाल नेहरु पर भी उन्होंने प्रचुर साहित्य की रचना की है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में उन्हें राष्ट्रकवि एवं पद्मभूषण के सम्मान से विभूषित किया गया।

माखनलाल चतुर्वेदी ने हिन्दी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में नये प्रतिमान स्थापित किये। 30 जनवरी, 1968 को उनका देहान्त हुआ।

प्रेरणा विमर्श 2020 के अवसर पर केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक सिने विमर्श और भारतीय विरासत का विमोचन करते लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिडला जी, गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक अन्त्योदय की ओर का विमोचन करते सह सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वरिष्ठ लेखिका अद्वैता काला जी व अन्य अतिथिगण

केशव संवाद पत्रिका के विशेषांक पत्रकारिता के अग्रदूत का विमोचन करते उत्तर प्रदेश के मा.राज्यपाल श्री राम नाईक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र संघचालक श्री सूर्यप्रकाश टोंक जी, माखनलाल चतुर्वेदी विवि. के पूर्व कुलपति श्री जगदीश उपासने जी व अन्य अतिथिगण